www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 10 | गोरखपुर, 31 अगस्त 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए हर संभव सहयोग देगी प्रदेश सरकार : योगी आदित्यनाथ

वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गत शुक्रवार को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों के निरीक्षण के लिए पहुंचे। यह उनका विश्वविद्यालय परिसर में तीसरा आगमन था।

विश्वविद्यालय परिवार ने विद्यार्थियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और स्वस्तिवाचन के बीच मुख्यमंत्री का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा, कुलसचिव राकेश कुमार और वित्त अधिकारी सहित आचार्यों ने उनका अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री योगी ने दुर्लभ पांडुलिपियों एवं उनके संरक्षण कार्यों की प्रगति का सूक्ष्मता से अवलोकन किया और कार्यों की गति और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की धरोहर इन पांडुलिपियों का संरक्षण एक सराहनीय कार्य है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

योगी ने स्पष्ट किया कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को संरक्षित करना आने वाली पीढ़ियों का महत्वपूर्ण दायित्व है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विस्तार भवन में भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन द्वारा चल रहे संरक्षण कार्यों की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने ऐतिहासिक सरस्वती भवन पुस्तकालय और अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली।

कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का तीसरी बार विश्वविद्यालय आगमन होना संस्कृत भाषा, विश्वविद्यालय और देववाणी के लिए गौरव और हर्ष की बात है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पांडुलिपियों के संरक्षण के इस अभियान को गति देने में विश्वविद्यालय पूरी तरह से तत्पर है।

▶ महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक जारी

40% शहरी महिलाओं को लगता है डर! नारी-2025 ने खोली सुरक्षा की पोल

नई दिल्ली। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक, नारी 2025, ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चौंकाने वाले आँकड़े उजागर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएँ अपने शहरों में असुरक्षित महसूस करती हैं, और खराब रोशनी और सुरक्षा के अभाव के कारण रात में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। इस अध्ययन में सभी राज्यों के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय ली गई है और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए एक आँकड़ा-आधारित ढाँचा प्रदान किया गया है।

निष्कर्षों के अनुसार, रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहरों के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में माना गया है। भारत में बड़ी संख्या में महिलाओं को सड़कों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें घूरना, छेड़खानी, अश्लील टिप्पणियाँ और शारीरिक स्पर्श शामिल हैं। इसके कारण कई छात्राएँ स्कूल छोड़ रही हैं या कामकाजी महिलाएँ अपनी नौकरी छोड़ रही हैं। सात प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि 2024 में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें 18-24 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं में सबसे अधिक जोखिम था। इसकी तुलना में, एनसीआरबी 2022 के आँकड़े महिलाओं के खिलाफ अपराध के केवल 0.07% मामलों की रिपोर्ट करते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, खराब रोशनी और अकुशल सार्वजनिक परिवहन के कारण महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों को असुरक्षित मानती हैं। यह धारणा सामाजिक दृष्टिकोण से और भी बढ़ जाती है जो अक्सर उत्पीड़न के लिए पीड़ितों को दोषी ठहराते हैं।

एनएआरआई 2025 की रिपोर्ट वह करती है जो आधिकारिक एनसीआरबी आँकड़े नहीं कर सकते: यह अप्रतिबंधित उत्पीड़न के 'अंधेरे आंकड़े' को भरती है, महिलाओं के दैनिक अनुभवों को संदर्भ और विवरण देती है, और सुरक्षा की वास्तविकता (केवल मामलों की संख्या नहीं, बल्कि धारणा) को सीधे सामने लाती है। कई महिलाएं उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट अधिकारियों को नहीं देतीं, क्योंकि उन्हें आगे और उत्पीड़न या सामाजिक कलंक का डर रहता है; केवल 22 प्रतिशत महिलाएं ही अपने अनुभवों की रिपोर्ट अधिकारियों को देती हैं तथा केवल 16 प्रतिशत मामलों में ही कार्रवाई की जाती है।

घर में भीषण विस्फोट, एक की मौत, जांच जारी

कन्नूर। कन्नूर की कन्नपुरम ग्राम पंचायत के कीझारा में शनिवार तड़के करीब 1.50 बजे एक शक्तिशाली विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे एक किराए का मकान जमींदोज हो गया। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पड़ोसियों ने बताया कि विस्फोट से 500 मीटर के दायरे में घर हिल गए। पंचायत सदस्य वी.वी. पुष्पावल्ली, जो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर रहती हैं, ने कहा मेरा घर हिल गया, और जब हम बाहर निकले, तो पहले तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद, हवा में बारूद की गंध फैल गई।

संदेह है कि इस घर का उपयोग अवैध रूप से विस्फोटक बनाने के लिए किया जा रहा था। पुलिस ने यह जानकारी दी। कण्णपुरम थाने के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट रात एक बजकर 50 मिनट पर एक किराए के घर में हुआ। अधिकारी ने बताया कि

▶ पुलिस को अवैध रूप से विस्फोटक बनाने का शक

धमाका इतना जोरदार था कि पूरा घर ढह गया और आसपास के चार घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।

पुलिस ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को इलाके से बची हुई विस्फोटक सामग्री को हटाने के लिए तैनात किया गया है। उसके बाद विस्तृत तलाशी ली जाएगी। धमाके के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मलबे में मानव अवशेष देखे हैं, हालांकि पुलिस ने अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि यह संपत्ति एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक की है।

पड़ोसियों ने बताया कि दो व्यक्ति किराए के मकान में रह रहे थे और अब तक उनकी पहचान नहीं हो सकी है। पड़ोसियों ने समाचार चैनलों को बताया कि वे आस-पड़ोस में किसी से ज्यादा मेल-जोल नहीं रखते थे और केवल रात में ही घर आते थे। पुलिस को संदेह है कि यह विस्फोट देसी बम या पटाखे बनाते समय हुआ और उसने बताया कि मामले की जांच जारी है।

उप्र सरकार ने रक्षा विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए 12,500 एकड़ भूमि आवंटित की: योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि देश में स्थापित किये जा रहे दो रक्षा औद्योगिक गलियारों में से एक उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है और राज्य सरकार ने इसमें रक्षा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए 12,500 एकड़ भूमि आवंटित की है।

मुख्यमंत्री ने नोएडा के सेक्टर 80 में राफे एमफाइबर प्राइवेट लिमिटेड के रक्षा उपकरण और इंजन परीक्षण केंद्र के उद्घाटन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गलियारे को अलीगढ़, कानपुर, आगरा और चित्रकूट समेत छह जिलों में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र को लखनऊ में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को

धन्यवाद दिया और कहा कि इस मिसाइल प्रणाली ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, भारत 1947 से ही चुनौतियों का सामना कर रहा है और इन चुनौतियों का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है। अगर आपके पास शक्ति है, तो दुनिया आपके सामने झुकती है। यह प्राचीन अवधारणा आज भी प्रासंगिक है।

योगी ने भारत के पारंपरिक ज्ञान का हवाला देते हुए कहा, ह्यह्यशस्त्र और शास्त्र के बीच संतुलन होना चाहिए। एक राष्ट्र इस संतुलन से ही शक्तिशाली बनता है, और शक्तिशाली बनने के बाद ही कोई शांति की अपील कर सकता है।

उन्होंने शक्ति और साहस के महत्व को रेखांकित करने के लिए महाराणा प्रताप की उक्ति, 'वीर भोग्या वसुंधरा' (वीरों को पृथ्वी विरासत में मिलती है) का भी उल्लेख किया। सिंह और योगी ने नोएडा में राफे एमफाइबर रक्षा विनिर्माण केंद्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

▶ अमित शाह का गला काटकर मेज पर रख देने मोइत्रा के बयान पर भाजपा सांसद संतोष पाण्डेय का तीखा पलटवार

'गृह मंत्री अमित शाह के लिए भड़काना निंदनीय है और दण्डनीय भी'

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता और सांसद संतोष पाण्डेय ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की उस टिप्पणी को अति निन्दनीय औकर दण्डनीय माना है जिसमें मोइत्रा ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटकर पीएम की मेज पर रख देने की बात कही है। संतोष पाण्डेय ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में अभद्रता और हिंसक वृत्ति का कोई स्थान नहीं है लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश में अराजकता फैलाने के अपने टूलकिट एजेंडे पर अमल कर रहे हैं और बिहार में राहुल गांधी की सभा के मंच से प्रधानमंत्री व उनकी स्वर्गस्थ माताजी के लिए अश्लील टिप्पणी के बाद टीएमसी सांसद मोइत्रा ने यह कहकर विपक्ष की कलुषित मानसिकता का परिचय दिया है। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने कहा, 'तेरा मेरा रिश्ता क्या, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा; कांग्रेस-टीएमसी का रिश्ता क्या, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। राजस्थान में इन्होंने कन्हैया और महाराष्ट्र में कोल्हे का गला उतारा आज देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए भड़काना निंदनीय है और दण्डनीय भी ह्र मोइत्रा का यह बयान बेहद आपत्तिजनक और लोकतांत्रिक संवाद का घोर अपमान है। यह आपत्तिजनक टिप्पणी उस व्यक्ति और टीएमसी की मानसिकता को दशार्ती है। मुख्य प्रदेश प्रवक्ता पाण्डेय ने सवाल किया कि क्या यह टीएमसी की आधिकारिक लाइन है? अगर नहीं, तो टीएमसी को मोइत्रा के कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए और मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। जब महुआ गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं, तो यह टीएमसी की हताशा और हिंसा की संस्कृति को उजागर करता है।

▶ सडक दुर्घटनाओं को कम करने कि दिशा में प्रयास जारी

एनएच पर बेतरतीब वाहन चलाने वाले 1.73 लोगों का 7 महीने में कटा चालान

नई दिल्ली। प्रमुख सड़कों खासकर एनएच पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार का कहना है कि वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50 फीसदी तक की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है।

सड़क दुर्घटना की सबसे प्रमुख कारणों में ओवर स्पीडिंग और नियमों की अनदेखी करना है। ट्रैफिक पुलिस के स्तर से की गई सघन जांच और बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। सिर्फ राज्य में मौजूद सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक यानी सिर्फ 7 महीने में नियमों की अनदेखी कर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वाले 1 लाख 73 हजार 143 लोगों के चालान कटे, जिससे 26 करोड़ 27 लाख रुपये जुमार्ना के तौर पर वसूला गया। इसमें सबसे ज्यादा ओवरस्पीडिंग या निर्धारित गति से अधिक स्पीड पर वाहन चलाने की वजह से चालान काटे गए हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाने, गलत ओवरटेकिंग करने समेत ऐसे अन्य सड़क से जुड़े नियमों का पालन सही तरीके से नहीं करने की वजह से जुमार्ना देना पड़ा है। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

मिजोरम को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने का ऐतिहासिक पल, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

आईजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल अब बैराबी-सैरांग रेल लाइन के उद्घाटन के साथ राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर 2025 को करेंगे। यह 51.38 किलोमीटर की रणनीतिक परियोजना कनेक्टिविटी को बदल देगी, यात्रा का समय कम करेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी, जिसमें कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल और 48 सुरंगें शामिल हैं जो चुनौतीपूर्ण पूर्वोत्तर इलाके को पार करती हैं। मिजोरम एक ऐतिहासिक मील के पत्थर की तैयारी कर रहा है क्योंकि बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन लगभग पूरी हो गई है, जिससे राज्य की राजधानी आइजोल पहली बार भारत के राष्ट्रीय रेलवे मानचित्र पर आ जाएगी। 51.38 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का उद्देश्य कनेक्टिविटी में बदलाव लाना, यात्रा के समय को कम करना और राज्य के लोगों के लिए नए अवसर खोलना है। यह लाइन पूर्वोत्तर के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों से होकर गुजरी है। इंजीनियरों ने 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबी 48 सुरंगों के साथ-साथ 142 पुलों का निर्माण किया है जिनमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की संरचनाएँ शामिल हैं।

इनमें से, पुल संख्या 196 की ऊँचाई 104 मीटर है, जो इसे दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कुतुब मीनार से भी ऊँचा बनाता है। यह इसे इस खंड का सबसे ऊँचा पुल और भारतीय रेलवे का दूसरा सबसे ऊँचा पुल बनाता है। इस परियोजना में निर्बाध परिवहन एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए पाँच सड़क ओवरब्रिज और छह सड़क अंडरपास भी शामिल हैं। परियोजना की

प्रगति उल्लेखनीय है, लगभग 95 प्रतिशत भौतिक कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और 97 प्रतिशत धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। मई 2025 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद जून में सुरक्षा निरीक्षण किया गया था।

रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने यात्री परिचालन के लिए लाइन को मंजूरी दे दी है और ट्रेनों को 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चलाने की अनुमति है। एक बार चालू हो जाने पर, नया मार्ग गुवाहाटी-आइजोल की यात्रा को 14-18 घंटे की सड़क यात्रा से घटाकर ट्रेन से लगभग 12 घंटे कर देगा। लाभ यात्रा सुविधा से कहीं अधिक हैं - तेज पहुँच से व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, साथ ही सीमावर्ती राज्य में रणनीतिक संपर्क भी मजबूत होगा।

इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा, जो मिजोरम के आधुनिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा। जनसंपर्क अधिकारी (एनएफआर) नीलांजम देव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इसकी आधारशिला रखी थी और 10 वर्षों के भीतर यह परियोजना पूरी हो गई। इसके साथ ही, मिजोरम भारतीय रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने वाला चौथा पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। आइजोल से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित नवनिर्मित सैरंग रेलवे स्टेशन, दो प्लेटफार्मों, तीन पटरियों और आधुनिक सुविधाओं के साथ राजधानी के रेल प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करेगा।

तीन दिवसीय व्याख्यानमाला संपन्न

मोहन भागवत ने जिज्ञासाओं का किया समाधान

नई दिल्ली। संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला '100 वर्ष की संघ यात्रा- नए क्षितिज' के अंतिम दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने कहा कि भारत अखंड है, यह जीवन का तथ्य है। पूर्वज, संस्कृति और मातृभूमि हमें एक करते हैं। अखंड भारत केवल राजनीति नहीं, बल्कि जनमानस की एकता है। जब यह भावना जागेगी तो सब सुखी और शांतिपूर्ण रहेंगे। संघ के बारे में यह धारणा गलत है कि वह किसी का विरोधी है। हमारे पूर्वज और संस्कृति समान हैं। पूजा-पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन पहचान एक है। भिन्न संप्रदायों में आपसी विश्वास कायम करने की आवश्यकता सभी पक्षों में है। मुसलमानों को यह आशंका छोड़नी होगी कि साथ चलने से उनका इस्लाम मिट जाएगा।

सरसंघचालक ने आजादी की लड़ाई और विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में संघ की भूमिका रेखांकित की। उन्होंने कहा कि सामाजिक आंदोलन में संघ कभी अलग से अपना झंडा नहीं उठाता। स्वयंसेवकों को खुली छूट है कि वह अच्छे काम जहां हो रहे हैं, वहां सहयोग करें।

घूँघट की बगावत

31 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू

मुहम्मद शाह ने नादिरशाह का मुकाबला करने के लिए खानदौरां और निजामुलमुल्क को अपना सेनापति नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने स्वयं को अयोग्य घोषित कर बादशाह की आज्ञा मानने से इंकार कर दिया। तब खुद बादशाह ने सेना की बागडोर संभाली और आक्रमणकारी का मुकाबला करने चल दिया।

औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। प्रशासनिक अयोग्यता और गद्दी के लिए खींचतान के कारण कोई भी शासक विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पा रहा था। सरदारों और दरबारियों के स्वार्थ पूर्ण रवैये से स्थिति और भी बिगड़ गई। चूंकि भारत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, इसलिए प्राचीनकाल से ही बाहरी आक्रमणकारी यहां धन के लोभ में आते रहते थे। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ जाने से एक बार फिर विदेशी आक्रमण का संकट पैदा होने लगा। इस बार यह आक्रमण मध्य एशिया से नहीं, फारस की ओर से हुआ।

फारस का बादशाह नादिरशाह मुगलों से कंधार पहले ही छीन चुका था। अब उसकी दृष्टि दिल्ली पर लगी थी। नादिरशाह का जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था। प्रारंभ में वह डकैतों का सरदार था। चूंकि उनका जीवन कष्टों और कठिनाइयों में बीता था, इसमें साहस तथा वीरता के गुण स्वाभाविक रूप से आ गए। अफगानों ने 1722 में शाह हुसैन सपावी से फारस छीन लिया था। नादिरशाह ने इसे वापस लेने में सहायता की और इस प्रकार शाही खानदान के निकट पहुंच गया। शाह हुसैन का पुत्र शाह तहमास्प अयोग्य हुआ और तब 1732 में उसे गद्दी से उतार कर नादिरशाह स्वयं बैठ गया। नादिरशाह 1732 में सेना लेकर भारत की ओर रवाना हुआ। इस आक्रमण के लिए, उसने बहाना बनाया कि मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने दिल्ली दरबार में फारस के राजदूत का अपमान किया।

मुगलों के उत्तरी-पश्चिमी सीमा की प्रतिरक्षा की ओर अत्यंत असावधान रहने के कारण नादिरशाह ने बड़ी आसानी से 1739 में गजनी, काबुल तथा लाहौर पर अधिकार कर लिया। जब नादिरशाह ने खैबर दर्रे को पार किया, तो लाहौर के गवर्नर जकारिया खान ने मुगल बादशाह मुहम्मद शाह को सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पत्र लिखा, किंतु उसने तथा उसके सामंतों ने लाहौर के गवर्नर की मदद की अपील को लापरवाही और अनादर के साथ ठुकरा दिया। जब नादिरशाह लाहौर तक आ पहुंचा, तब उनकी आंखें खुलीं। मुहम्मद शाह ने नादिरशाह का मुकाबला करने के लिए खानदौरां और निजामुलमुल्क को अपना सेनापति नियुक्त किया, लेकिन उन्होंने स्वयं को अयोग्य घोषित कर बादशाह की आज्ञा मानने से इंकार कर दिया। तब खुद बादशाह ने सेना की बागडोर संभाली और आक्रमणकारी का मुकाबला करने चल दिया।

करनाल में नादिरशाह की फौज ने मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। उधर अवध का नवाब सआदत खां बिना तैयारी किए ही लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। उसे हराकर कैद कर लिया गया। खानदौसं बुरी तरह घायल हुआ। मरणासन्न स्थिति में उसने आनेवाले खतरों को जानते हुए अपने दोस्तों से कहा कि जैसे हो नादिरशाह को दिल्ली से बाहर ही रखना। उसे कुछ देकर तत्काल वापस जाने के लिए बहला-फुसला लेना, किंतु इस नेक सलाह को मुहम्मद शाह के सरदार और सामंत गंभीरता से नहीं समझ पाए। हारने के बाद मुगलों के खेमों में भगदड़ मच गई। निजाम ने मध्यस्थ का काम किया। उसने नादिरशाह को दो करोड़ रुपये देकर ईरान जाने के लिए राजी कर लिया। निजाम से प्रसन्न होकर मुगल सम्राट ने उसे अमीर-उल-उमरा' का खिताब देकर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह देख सआदत खां ईर्ष्या व द्वेष से जल उठा। वह अकेले में नादिरशाह से मिला। उसने ईरानी बादशाह से कहा-'हुजुर, दो करोड़ जैसी छोटी रकम से आप कैसे संतुष्ट हो गए? इतनी छोटी रकम तो किसी भी प्रांत का गवर्नर अपने घर से दे सकता है।' सुनते ही नादिरशाह की आंखों में दिल्ली का अपार धन-वैभव दपदपाने लगा। विजयी नादिरशाह व दिल्ली का अपमानित मुगल सम्राट बादशाह मुहम्मद शाह, दोनों इकट्ठे ही दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही नादिरशाह ने दीवाने-खास के समीप राजमहल पर अधिकार कर लिया। पहले तो राजधानी में कोई अव्यवस्था नहीं थी, परंतु कुछ शरारती लोगों ने नादिरशाह की मृत्यु की अफवाह फैला दी। इससे दंगा शुरू गया, जिसमें कुछ फारसी सिपाही मारे गए। आधी रात में नादिरशाह के सेनाधिकारी डरते और कांपते उसके पास पहुंचे और उसे इस बारे में बताया। सुबह होते ही नादिरशाह घोड़े पर सवार होकर शहर में गया। वहां उसने गलियों में ईरानी सैनिकों की लाशें देखीं। रोशनुद्दौला की सुनहरी मस्जिद के पास कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंकें। बंदूक की गोली से एक ईरानी सेनानी भी मर गया। अपने सैनिकों की लाशें देखकर वह गुस्से से बिफर उठा । .11 मार्च, 1739 को प्रातः नौ बजे क्रोधाग्नि में जलते हुए उसने हुक्म दिया कि ईरानियों की हत्या करने के बदले में दिल्ली की जनता को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। आज्ञा मिलते ही हजारों सैनिक निरीह जनता पर टूट पड़े। चांदनी चौक, सब्जी मंडी, दरीबा कलां और जामा मस्जिद के आसपास के मकानों में आग लगा दी गई। आतंकित बच्चे और औरतें धू-धूकर जलने लगे। भागने वाले लोग भालों, तलवारों और तीरों से धराशायी कर दिए गए। निरंतर पांच घंटे तक नृशंसता का यह तांडव और चलता रहा।

नादिरशाह ने मुहम्मद शाह के अमीर-उमराव के अनुरोध पर ही अपने सैनिकों को कत्लेआम का आदेश दिया। इतिहासकार फ्रेका का कहना है कि उस दिन लगभग दो लाख व्यक्तियों का खून- खच्चर हुआ होगा, जबकि प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार, मरने वालों की संख्या लगभग 20,000 रही होगी। शहर की लूट के अतिरिक्त लाल किले में रखे शाही जवाहरात, सोना-चांदी और बहुमूल्य सामान विजेताओं ने हथिया लिया।

शाहजहां द्वारा बनवाए गए बेशकीमती 'मयूर- सिंहासन तथा अमूल्य कोहिनूर हीरे को भी लूटकर नादिरशाह ईरान ले गया। इस प्रकार नादिरशाह ने मुगलों द्वारा संचित 348 वर्षों की अपार संपत्ति को क्षणभर में लूट लिया। इतिहासकारों का कहना है कि लगभग 50 करोड़ रुपये के जवाहरात, एक करोड़ रुपये का सोना, 60 लाख रुपये तथा लाखों अशर्फियां नादिरशाह के हाथ लगीं। उसने 57 दिन तक अपनी सेना सहित दिल्ली को जी भरकर लूटा और जाते वक्त 70 करोड़ रुपये मूल्य के सोना चांदी जवाहरात के अतिरिक्त 100 हाथी 7000 घोड़े, 10,000 ऊंट, 100 नाजिर, 130 लेखक, 200 सुनार, 300 कारीगर तथा 200 बढ़ई भी अपने साथ ले गया।

महिलाएं गढ़ेंगी आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा

अब गोबर से बनाएंगी पेंट

झांसी। महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा लिखने जा रही हैं। वह अब गोबर से पेंट बनाएंगी। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अभी तक खाद्य तेल, खाद्यान्न, परिधान, पशु आहार के क्षेत्र में काम कर रही थीं लेकिन यह जनपद का पहला प्लांट होगा, जहां गोबर से पेंट बनाया जाएगा। इसका उपयोग सरकारी भवनों में किया जाएगा। वहीं, दीपावली में यह बाजारों में भी उपलब्ध होगा। चिरगांव की ग्राम पंचायत गुलारा की गोशाला में करीब 40 लाख रुपए की लागत से शुरू हुए इस प्लांट में तीन कमरों के साथ ही मशीनें लगाई गई हैं। गोवर्धन प्रेरणा महिला लघु उद्योग समिति की ओर से शुरू किए गए इस कार्य में 20 महिलाओं का समूह कार्य करेगा। समूह की अध्यक्ष पुष्पा योगी ने बताया कि इस प्राकृतिक पेंट के उपयोग से गर्मी के दिनों में कमरे का तापमान कम रहेगा। छोटे-मोटे कीड़े नहीं आएंगे। शुगर, अस्थमा जैसी बीमारियां घर में नहीं पनपेंगी। इस पेंट की कीमत भी कम रहेगी। प्लांट का उद्घाटन प्रकाश पाल (क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा कानपुर) ने किया। इस दौरान विधायक राजीव सिंह पारीछा ने कहा कि यह उद्योग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम ने कहा कि गाय के गोबर का जब उपयोग होगा तो निश्चित ही अन्ना प्रथा पर अंकुश लगेगा । इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में इसकी कारगर भूमिका रहेगी।

शहर के खूंखार कुत्तों को एकल बैरक में रखा जाएगा

वाराणसी। खूंखार कैदी की तरह शहर के खूंखार कुत्तों को एकल बैरक में रखा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था नगर निगम ने बनाई है। ऐढ़े में बनकर तैयार एबीसी सेंटर में 40 एकल और 10 सामूहिक बैरक टाइप बनाए गए हैं। एकल में एक और सामूहिक में 10 कुत्ते साथ रहेंगे। एकल बैरक में खूंखार और रैबीज वाले कुत्ते को रखकर इलाज किया जाएगा जबकि सामूहिक में सामान्य कुत्तों का इलाज किया जाएगा। इसके बाद कुत्तों का व्यवहार सामान्य होने पर जहां से उठाया जाएगा वहीं लाकर छोड़ा जाएगा। निगम कुत्तों का बंध्याकरण करेगा। इसके लिए लालपुर-ऐढ़े क्षेत्र में एक अत्याधुनिक एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर का निर्माण किया गया है। सेंटर में दरवाजे, खिड़कियों समेत सभी सुविधाएं हैं। इस–के अगले माह से संचालन शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए टेंडर हो चुका है।

इस सेंटर के संचालन की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग पद्धति से सौंपी जाएगी। जिसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। खास बात यह है कि इस सेंटर में

एक दिन में 30 से अधिक कुत्तों के बंध्याकरण की व्यवस्था होगी, जिससे आवारा कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

1.82 करोड़ रुपये की लागत से एक एकड़ भूमि पर निर्मित यह सेंटर वाराणसी का पहला बड़ा और व्यवस्थित एबीसी केंद्र होगा। यहां कुत्तों के लिए कुल 40 एकल बैरक बनाए गए हैं, जबकि बंध्याकरण उपरांत निगरानी और विश्राम के लिए 10 सामूहिक बैरक भी तैयार किए गए हैं। इस भवन के भूतल पर पांच कमरे, दो किचन, दो शौचालय और एक बेसिंग रूम तैयार किया गया है। प्रथम तल पर भी दो कमरे, एक किचन और एक शौचालय की सुविधा है। इसके अतिरिक्त सेंटर में एक ऑपरेशन थिएटर (ओटी), वैक्सीनेशन सेंटर, फीडिंग रूम, पैथोलॉजी और एक्स-रे कक्ष जैसी मेडिकल सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी।

कुत्तों के लिए हर जिले में एसपीसीए है। इसका फुल फॉर्म सोसाइटी फार द प्रिवेंशन आफ क्रूएलिटी टू एनिमल है। हिंदी में इसे पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी कहते हैं। इसकी स्थापना 1824 में इंग्लैंड में हुई थी। ये पशु कल्याण के लिए अभियान चलाते हैं। इसमें पशु चिकित्सा, पालन और जिम्मेदार अधिकारी शामिल हैं। जो समाज में पशुओं पर होने वाली क्रूरता पर कंट्रोल करने और पशुओं से समाज की रक्षा करने का कार्य करते हैं।

सूचना 1533 पर दें

कुत्ते से जुड़े किसी भी प्रकार की सूचना नगर निगम के कंट्रोल रूम 1533 पर दी जा सकती है। आने वाले दिनों में शहर के बाहर 200 एकड़ भूमि की तलाश की जा रही है। जहां पर एक साथ 2000 कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी। इसके लिए रामनगर, पिसौर, फुलवरिया में जमीन देखी गई है।

एबीसी सेंटर का संचालन जल्द शुरू होगा। इसमें खूंखार, रैबीज व सामान्य कुत्तों के लिए अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं। जहां उनका इलाज होगा। इलाज के बाद उन्हें जहां से लाया जाएगा वहां छोड़ दिया जाएगा।

–डॉ संतोष पाल,
पशु चिकित्साधिकारी, नगर निगम

जैविक कचरे का अस्पतालों में लगा ढेर, मशीनें खटारा

- **महापौर ने जताई नाराजगी**
- **जल शोधन के लिए लगा ईटीपी प्लांट बंद मिला**

कानपुर। कानपुर समेत आठ जिलों के हजारों अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का बोझ मेडिकल पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी (एमपीसीसी) में लगी खटारा मशीनें (इंसीनेटर) नहीं उठा पा रही हैं। इसके चलते भौंती स्थित प्लांट में खुले में जैविक कचरे का ढेर लगा है। बिठूर स्थित विलवर्ल्ड कंपनी में भी जैविक कचरे का समुचित निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इसके चलते उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने शुक्रवार को दोनों कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

बुधवार को महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त सुधार कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निस्तारण के संबंध में बैठक हुई थी। इसमें सामान्य कूड़े के साथ मेडिकल कचरा फेंके जाने पर महापौर ने नाराजगी जताई थी। इसके अगले दिन ही पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारियों ने दोनों कंपनियों के प्लांट का निरीक्षण किया। एमपीसीसी प्लांट में कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, उन्नाव, कन्नौज, इटावा, फतेहपुर और हमीरपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी और क्लीनिक के जैविक चिकित्सा अपशिष्ट (बायो मेडिकल वेस्ट) को इकट्ठा कर उनका निस्तारण किया जाता है। कंपनी के 14 वाहन प्रतिदिन मेडिकल वेस्ट प्लांट लाते हैं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों

को कई साल पुरानी मशीनें लगी मिलीं। एमपीसीसी में लगा इंसीनेटर निर्धारित क्षमता से कम पर चलता मिला। कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि प्लांट के अपग्रेडेशन का काम शुरू करा दिया गया है। जल्द ही नई मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा प्लांट में जल शोधन के लिए लगा ईटीपी प्लांट बंद मिला। पता चला कि इसकी मोटर खराब है। प्लांट के सुपरवाइजर प्रीतम प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सके। कमोबेश यही स्थित विलवर्ल्ड की भी मिली।

पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार सुमन ने बताया कि क्षमता से अनुरूप वेस्ट का निस्तारण न होने से प्लांट में मेडिकल कचरा डंप है।कमियां मिलने पर दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद अधिकारी फिर निरीक्षण करेंगे। सुधार न मिलने पर दोनों कंपनियों पर मुख्यालय स्तर से जुमार्ना लगाने समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी।

फसल नष्ट होने की आशंका के चलते किसान मायूस हुए किसान

तिलोई/सिंहपुर/शाहगढ़। लगातार हो रही बारिश के चलते आठ ड्रेनें उफान पर हैं, जिसकी वजह से 100 से अधिक गांवों के किसानों की 12 हजार बीघे फसल जलमग्न हो गई है। ड्रेनों की सफाई न होने के चलते किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। फसल नष्ट होने की आशंका के चलते किसान मायूस हो गए हैं।

पखवारे भर से हो रही बारिश से ड्रेनों में जमा पानी निकलने की बजाय खेतों में भर गया है। भुसैला, मूंगताल, इन्हौना, गुमिया, हंसवा, अड़वारा और अब्दहा ड्रेन उफान पर हैं। 10 किमी लंबी भुसैला ड्रेन से सात गांवों के किसानों की एक हजार बीघे फसल डूब गई है। 40 किमी लंबी मूंगताल ड्रेन से 12 गांवों के किसानों की 1,300 बीघे फसल डूब गई है।

वहीं, 30 किमी लंबी इन्हौना ड्रेन से 14 गांवों के किसानों की 1,400 बीघे फसल डूब गई है। 45 किमी लंबी गुमिया ड्रेन से 16 गांवों के किसानों की 2,600 बीघे फसल डूब गई है। आठ किमी लंबी अब्दहा ड्रेन से पांच गांवों के किसानों की 500 बीघे फसल डूब गई है। आठ किमी लंबी हंसवा ड्रेन से पांच गांवों के किसानों की 700 बीघे फसल जलमग्न हो गई है।

छह किमी लंबी अड़वारा ड्रेन से 10 गांवों के किसानों की 800 बीघे फसल डूबकर लगभग नष्ट हो चुकी है। 52 किमी लंबी गुलालपुर ड्रेन के उफनाने से शाहगढ़

बारिश से फसलों के प्रभावित होने की जानकारी पर हल्का लेखपाल को निर्देश दिया गया है। जल्द ही नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेज कर किसानों को मुआवजा राशि दिलाई जाएगी।
- अर्पित गुप्ता, एडीएम

क्षेत्र के 20 गांवों की करीब तीन हजार बीघे फसल सड़ने की स्थिति में पहुंच गई है।

किसान सुरेंद्र सिंह के मुताबिक पूरे नन्हू दुबे, पूरे हरपाल बैस, हरिहरपुर, राजस्व ग्राम जगदीशपुर, पूरे बढ़ई, पूरे लखपति व राजस्व ग्राम टोडरपुर के किसानों की फसल खराब हो गई है। किसानों के अनुसार अब्दहा ड्रेन की खोदाई लगभग 10 वर्षों से नहीं कराई गई है। खेखरुआ निवासी किसान नरसिंह बताते हैं कि बारिश बंद होने के बाद पानी कम होता है, लेकिन फिर से बारिश होने से पहले वाली स्थिति हो जाती है। जलभराव रहने से धान की फसल बर्बाद हो गई है।

डबल इंजन सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद पर काम किया

प्रतापगढ़ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मेडिकल कॉलेज, आंवला और रसमलाई से प्रतापगढ़ को जाना जाता है जबकि विपक्षी सरकारों ने एक जनपद एक माफिया दिया। इसके बदले डबल इंजन सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद पर काम किया। इसका नतीजा है कि प्रतापगढ़ के आंवले को आज देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान मिली। इससे पहले उन्होंने प्रतापगढ़ और कौशाम्बी संसदीय क्षेत्र को 570 करोड़ की 186 परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही पीएम और सीएम आवास जुड़े लोगों को चाबियां और स्वयं सहायता से जुड़े समूहों को प्रमाणपत्र प्रदान किया।

जीआईसी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अन्नदाता किसानों ने अमृत फल आंवला की खेती से आरोग्यता को बढ़ावा देकर देश दुनिया में जनपद को पहचान दिलाई है। वहीं सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने रसमलाई की मिठास को घर-घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने मंच से ही विधायक से कहा कि वो क्षेत्रीय जनता को भी रसमलाई की दावत दें।

उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि प्रतापगढ़ में कनेक्टिविटी की समस्या है, उस जिले के 40 किमी. भू-भाग को शामिल करते हुए देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहा है। अयोध्या से प्रयागराज के बीच छह लेन हाईवे मार्ग के साथ बाईपास विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सोनेलाल पटेल के नाम पर स्थापित मेडिकल कॉलेज भी जनपद की पहचान बना हुआ है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ पात्रों को दिया जा रहा है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 310 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले 70 कार्यों का शिलान्यास बटन दबाकर किया। वहीं 260 करोड़ की लागत से तैयार 116 कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण और शिलान्यास वाले कार्यों का सीएम ने अपने संबोधन में भी भी उल्लेख किया।

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। शहर की सड़कों का प्रमुखता से सुदढ़ीकरण किया जाएगा ताकि सड़कें दूर से ही चमकें।

लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम को भाजपा ने राष्ट्रीय पर्व की तरह ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया। इसके तहत जनसभा पंडाल को इस बार भगवा में नहीं, बल्कि तिरंगा मय कर दिया गया था। पंडाल की शोभा बढ़ाने के लिए रंगीन छतरियों और पतंगों को भी सजाया गया। जनसभा की खासियत रही कि इस बार मुख्यमंत्री जैसे इस ऐतिहासिक पल को स्मृति में संजोना चाह रहे थे। उन्होंने जनता जनार्दन का अभिवादन जय श्रीराम के नारों से नहीं बल्कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से किया। बावजूद इसके पूरा पंडाल जय श्रीराम के नारों से गुंजायमान रहा।

मुख्यमंत्री के स्वागत भाषण में सदर विधायक राजेंद्र मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर राजनीतिक संदेश भी दिया। उन्होंने सीएम के समक्ष मंच से खुद को जनपद का इकलौता सेवक बताया। दरअसल, सात विधानसभा क्षेत्रों में महज सदर से ही भाजपा को जीत मिली है। इसके पूर्व प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री को गणेश प्रतिमा भेंटकर अभिवादन किया। राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रयागराज की उदघोषिका रंजना त्रिपाठी ने किया।

मंच पर पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह, पूर्व मंत्री प्रो. शिवाकांत ओझा, एमएलसी उमेश द्विवेदी, पूर्व विधायक धीरज ओझा, पूर्व विधायक राम शिरोमणि, नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमलता सिंह, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, पूर्व सांसद संगमलाल गुप्ता, जिला प्रभारी कौशलेंद्र पटेल, जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव मौजूद रहे।

तीरंदाजी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे कोच लल्लन

कानपुर । भीतरगांव में तीरंदाजी का निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी दो दर्जन बालक बालिका प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । प्रशिक्षण कोच लल्लन द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। निशुल्क तीरंदाजी प्रशिक्षण से स्थानीय स्कूल और लाइब्रेरी के प्रशासक भी रुचि ले रहे हैं।

घूँघट की बगावत

31 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

दुनिया के लिये अपनेपन का नजरिया विकसित करना होगा, सौदे का नहीं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित वार्षिक व्याख्यानमाला केवल एक उत्सव मात्र नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की आत्मा और उसके भविष्य की एक गहन घोषणा थी। संघ सरचालक मोहन भागवत ने इन व्याख्यानों में जिस स्पष्टता और गंभीरता से अपने विचार रखे, उन्होंने संघ की विचारधारा के प्रति व्याप्त भ्रांतियों का निवारण करने के साथ-साथ भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में एक नया क्षितिज भी उद्घाटित किया। यह आयोजन संघ के सौ वर्ष की साधना का मूल्यांकन ही नहीं, बल्कि आने वाले सौ वर्षों की दिशा का भी उद्घोष था। नई इबारत लिखते हुए भागवत ने स्पष्ट कहा कि संघ की कार्यप्रणाली का सार है,नए मनुष्य का निर्माण। यह विचार सुनने में सरल लग सकता है, किंतु इसके निहितार्थ अत्यंत गहरे हैं। समाज और राष्ट्र की सारी समस्याओं का मूल व्यक्ति के भीतर छिपा है। इसीलिये देश के सभी वर्गों को एकसूत्र में जोड़ने के संकल्प के साथ संघ आगे बढ़ेगा क्योंकि जब तक व्यक्ति का चरित्र, दृष्टि और आचरण नहीं बदलते, तब तक कोई भी व्यवस्था स्थायी रूप से परिवर्तित नहीं हो सकती। संघ व्यक्ति-निर्माण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को बदलने की दीर्घकालिक साधना कर रहा है। यही कारण है कि संघ के कार्य का परिणाम केवल शाखाओं या कार्यक्रमों में नहीं मापा जा सकता, बल्कि उस अदृश्य लेकिन ठोस नैतिक शक्ति में देखा जा सकता है, जो धीरे-धीरे समाज की दिशा बदल रही है।

हिंदुत्व को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती रही हैं, उन्हें भी भागवत ने तार्किक ढंग से दूर किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व किसी संकीर्ण परिभाषा का नाम नहीं है। यह कोई धर्म विशेष की पूजा-पद्धति या संप्रदाय नहीं है। हिंदुत्व भारतीय जीवन दृष्टि है, वह व्यापक सांस्कृतिक धारा है, जिसमें करुणा, समरसता, सेवा, अहिंसा, सत्य और आत्मानुभूति का सम्मिलन है। हिंदुत्व सबको जोड़ता है, किसी को अलग नहीं करता। यह भारत की आत्मा है और इसी आत्मा के बल पर भारत को विश्वगुरु बनने की पात्रता प्राप्त हो सकती है। इस स्पष्ट व्याख्या ने उस संदेह को भी दूर किया कि संघ का हिंदुत्व राजनीतिक या सत्ता प्राप्ति का साधन है। वास्तव में यह संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में बांधने वाली दृष्टि है, जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। दूसरे दिन के वक्तव्य में भागवत ने और गहराई से विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने पंचकर्म की चर्चा करते हुए कहा कि जैसे आयुर्वेद में पंचकर्म शरीर की शुद्धि का साधन है, वैसे ही समाज की शुद्धि और पुनर्निर्माण के लिए भी पंचकर्म आवश्यक है। उन्होंने पांच आयाम बताए-चरित्र निर्माण, संगठन निर्माण, समरसता, गरीब का उत्थान और आध्यात्मिक जागरण। यह पांचों पहलू किसी भी समाज के स्थायी स्वास्थ्य और विकास के आधार हैं। केवल राजनीतिक सुधार या आर्थिक प्रगति से राष्ट्र महान नहीं बनता, बल्कि तब बनता है जब व्यक्ति का चरित्र शुद्ध हो, समाज संगठित हो, उसमें समरसता हो, कमजोर वर्ग को उत्थान मिले और राष्ट्र का जीवन उच्च आध्यात्मिक मूल्यों से संपन्न हो।

विशेष रूप से गरीब आदमी के उत्थान पर भागवत का जोर उल्लेखनीय था। उन्होंने कहा कि भारत तभी सशक्त होगा जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक सम्मान और अवसर पहुंचे। यह विचार महात्मा गांधी के 'अंत्योदय', विनोबा भावे के 'सर्वोदय' और दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' की पुनर्स्मृति कराता है। आधुनिक भारत की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकास के लाभ समाज के सभी तबकों तक समान रूप से नहीं पहुंचते। अमीर-गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। यदि इस खाई को नहीं भरा गया, तो राष्ट्र की प्रगति अधूरी रह जाएगी। भागवत का दृष्टिकोण यह है कि राष्ट्र तभी महान बन सकता है जब उसका सबसे कमजोर नागरिक भी गरिमा और सम्मान के साथ जीवन जी सके। धर्मों की

भागवत के विचार निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक परंपरा और संघ की कार्यप्रणाली को नई स्पष्टता देते हैं, लेकिन यहां यह प्रश्न भी उठता है कि इन विचारों को व्यवहार में उतारने की राह कितनी सरल है? समाज की जटिलताओं, जातीय और धार्मिक तनावों, राजनीतिक स्वार्थों और आर्थिक विषमताओं के बीच नया मनुष्य बनाना एक दीर्घकालिक साधना है।

एकता पर उनका दृष्टिकोण भी उतना ही महत्वपूर्ण था। भारत का इतिहास यही बताता है कि यहां विविधता में एकता की परंपरा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन-सभी धर्म इस भूमि पर फले-फूले हैं और सभी का मूल संदेश करुणा, सेवा और मानवता रहा है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को सत्ता की राजनीति से जोड़ा जाता है। भागवत का कहना था कि यदि हम धर्मों के मूल्यों को देखें तो उनमें कोई टकराव नहीं है। सबका आधार प्रेम, सत्य और सेवा है। यही साझा आधार भारत को एक ऐसा समाज बनाने में सक्षम है, जो विश्व के लिए अनुकरणीय हो।

भागवत के विचार निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक परंपरा और संघ की कार्यप्रणाली को नई स्पष्टता देते हैं, लेकिन यहां यह प्रश्न भी उठता है कि इन विचारों को व्यवहार में उतारने की राह कितनी सरल है? समाज की जटिलताओं, जातीय और धार्मिक तनावों, राजनीतिक स्वार्थों और आर्थिक विषमताओं के बीच नया मनुष्य बनाना एक दीर्घकालिक साधना है। आलोचक कहते हैं कि संघ के पास विचार तो हैं, लेकिन उनकी जड़ें अभी तक समाज के सभी वर्गों तक गहराई से नहीं पहुँची हैं। विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों में संघ के प्रति संदेह आज भी विद्यमान है। इसलिए केवल वक्तव्यों से नहीं, बल्कि ठोस और पारदर्शी कार्यों से यह भरोसा पैदा करना होगा कि संघ का हिंदुत्व वास्तव में सर्वसमावेशी है। इसी तरह गरीब के उत्थान और धर्मों की एकता की बातें विचारणीय हैं, किंतु यह भी देखना होगा कि क्या संघ और उससे जुड़े संगठन इस दिशा में ठोस योजनाएं और परिणाम दे पा रहे हैं? आलोचक यह प्रश्न उठाते हैं कि विकास की मुख्यधारा में गरीबों की स्थिति सुधारने में सामाजिक संगठनों से अधिक भूमिका सरकार की रही है। अतः यदि संघ इन बिंदुओं को अपनी कार्ययोजना का मूल बनाए, तो उसे केवल नैतिक आह्वान से आगे बढ़कर व्यावहारिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने होंगे। तभी यह दृष्टि प्रभावी सिद्ध होगी और भारत सचमुच उस दिशा में बढ़ सकेगा, जिसकी परिकल्पना व्याख्यानमाला में की गई।

आज की वैश्विक परिस्थितियों पर दृष्टि डालें तो भागवत के विचार और भी प्रासंगिक हो उठते हैं। दुनिया हिंसा, आतंकवाद, युद्ध और उपभोक्तावाद की अंधी दौड़ से त्रस्त है। पर्यावरण संकट दिन-प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है। मानसिक तनाव और आत्मकेंद्रित जीवन-शैली ने मानव को भीतर से खोखला कर दिया है। इन परिस्थितियों में भारत ही वह देश है, जो एक वैकल्पिक जीवन-दर्शन दे सकता है। भारत के पास भौतिक विकास के साथ-साथ आध्यात्मिक समृद्धि की धरोहर है। यही धरोहर भारत को विश्वगुरु बनने की पात्रता प्रदान करती है। संघ की शताब्दी वर्ष की यह व्याख्यानमाला केवल संघ के स्वयंसेवकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश और विश्व के लिए एक संदेश है। यह संदेश है-नए मनुष्य का निर्माण करना, गरीब को उठाना, धर्मों को जोड़ना, समाज में समरसता स्थापित करना और हिंदुत्व की व्यापक जीवन दृष्टि के आधार पर विश्व को दिशा देना। यह केवल भाषण नहीं, बल्कि एक संकल्प है। यदि भारत को सचमुच विश्वगुरु बनना है, तो यह संकल्प पूरे समाज का होना चाहिए।

संघ को लेकर लंबे समय से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उसकी विचारधारा संकीर्ण है, वह केवल बहुसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई स्थान नहीं है। भागवत के इन वक्तव्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि संघ का दृष्टिकोण न तो संकीर्ण है और न ही बहिष्कृत करने वाला। संघ का हिंदुत्व सर्वसमावेशी है, जिसमें सभी धर्म और सभी आस्थाएं स्थान पा सकती हैं। इसका उद्देश्य सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि समाज का नैतिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण है। संघ की शताब्दी का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज भारत का भविष्य एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर आर्थिक प्रगति, तकनीकी उपलब्धियां और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा है, तो दूसरी ओर आंतरिक चुनौतियां भी हैं-सामाजिक असमानता, जातीय तनाव, धार्मिक विद्वेष और मूल्यहीन राजनीति। इन चुनौतियों का समाधान केवल बाहरी सुधारों से नहीं, बल्कि भीतर से परिवर्तन लाने से होगा। यही संघ की कार्यप्रणाली है और यही भागवत का संदेश है। नये क्षितिज की ओर व्याख्यानमाला एक निष्कर्ष की ओर ही नहीं, बल्कि एक प्रश्न की ओर भी ले जाती है, क्या हम भारत को केवल भौतिक अर्थों में शक्तिशाली बनाना चाहते हैं या उसे वास्तव में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं? यदि उत्तर दूसरा है, तो हमें भागवत के सन्देश को क्रियान्वित का धरातल देना ही होगा। दुनिया के लिये अपनेपन का नजरिया विकसित करना होगा, सौदे का नहीं।

घूंघट में आईं महिलाओं ने किया उपद्रव, पुलिस कर्मियों को दिखाए चप्पल

गोरखपुर। आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी की मौत की खबर पर रामपुर नया गांव से हॉस्पिटल के बाहर घूंघट में पहुंचीं महिलाओं ने उपद्रव शुरू कर दिया था। महिला पुलिस कर्मियों ने जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। दो दरोगा को महिलाओं ने खींचने की कोशिश भी की। इसके बाद जबरिया अस्पताल परिसर में घुसने की कोशिश की। इसी बीच भीड़ में मौजूद कुछ महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को चप्पल भी दिखाए। पुलिस कर्मियों ने उनका वीडियो भी बनाकर रख लिया है। इस बीच कुछ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे आप नेता कुंज बिहारी की मौत हो गई। भाई मनोज कुमार निषाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत कराया। मौत के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए एंबुलेंस में रखने के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने परिजनों और लोगों को गुमराह करते हुए कहा कि पुलिस मामले को हादसे का रूप दे रही है। यह जानकारी मिलते हुए भीड़ उग्र हो गई। इसके बाद धक्का-मुक्की करते हुए शव को एंबुलेंस से बाहर निकालने की कोशिश की। इस पर एसआई अनूप सिंह ने झूठी सूचना की बात कहते हुए उन्हें शांत होने की अपील की लेकिन वे मारपीट पर उतारू हो गए। यहीं नहीं भीड़ के साथ घूंघट में पहुंचीं महिलाओं ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता करते हुए चप्पल दिखाकर माहौल और बिगाड़ने की कोशिश की। इस दौरान कुछ ने जबरिया अस्पताल परिसर में घुसने की भी कोशिश की। हालात बिगड़ता देख मौके पर तैनात महिला पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए किसी तरह स्थिति को काबू किया तो कुछ ने पथराव शुरू कर दिया। इससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर उपद्रवी महिलाओं की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कुंज बिहारी की मौत की खबर पर पहुंचे परिजनों और मोहल्लेवालों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि इलाज में लापरवाही के कारण कुंज बिहारी की जान गई है। भीड़ ने परिसर में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और अस्पताल की खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर में तोड़फोड़ की जाने लगी। अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। गोरखनाथ थाना प्रभारी के साथ-साथ आसपास के कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों और भीड़ को समझाने की कोशिश की लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। परिजन मांग कर रहे थे कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस बीच आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष

विजय श्रीवास्तव भी पहुंच गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जब पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तो मामला और बिगड़ गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस टीम पर ईंट-पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पथराव में गोरखनाथ थाना प्रभारी शशिभूषण राय का सिर फूट गया। वहीं एसआई रिषभ सिंह, अनूप सिंह व चिलुआताल थाने में तैनात एसआई हैप्पी सिंह को चोटें आईं। इधर अस्पताल के पास खड़े पांच अन्य राहगीर भी पथराव में घायल हो गए। साथी पुलिस कर्मियों ने घायल थाना प्रभारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां टांके लगाने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। सर्किल की फोर्स व पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने हालात को नियंत्रित किया और परिजनों को शांत कराया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आश्वासन दिया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मृतक कुंज बिहारी तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे। बड़े भाई मनोज निषाद और छोटे भाई-बहन सरोज हैं। पत्नी रिंकी देवी और बच्चे दिव्यांशु व अयांश का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने आरोप लगाया कि एक ओर हमलावरों ने बेरहमी से हमला कर कुंज बिहारी की जान ली, दूसरी ओर अस्पताल ने समय पर उचित इलाज नहीं किया। घटना के बाद अस्पताल व गांव में तनाव व्याप्त है। एहतियात के तौर पर अस्पताल के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। वहीं प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। मृतक कुंज बिहारी राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। ऐसे में घटना ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आम आदमी पार्टी से जुड़े स्थानीय नेताओं ने प्रशासन पर लापरवाही और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं, अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी घटना की निंदा की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। हंगामा और पथराव के दौरान पुलिस कर्मियों ने कई वीडियो बनाए। इसके जरिये भीड़ को उकसाने और पथराव करने वालों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अब तक राजन निषाद, संजय निषाद, गोलू , जुगनू कुमार, अवधेश निषाद, रमेश समेत 12 से अधिक उपद्रवियों की पहचान कर ली है। पुलिस जल्द ही अन्य उपद्रवियों की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।

यह हुआ था विवाद

रामपुर नयागांव निवासी कुंजबिहारी निषाद अपने भाई मनोज कुमार निषाद के साथ बिल्डिंग मटेरियल की दुकान चलाते थे। बीते 23 अगस्त को उनका साला हेमंत गांव के पास मकान बनवा रहे अभिषेक से 4200 रुपये बकाया लेने के लिए भेजा था। जहां अभिषेक ने यह कहकर लौटा दिया कि दूसरे स्थान से सस्ता मटेरियल मिल रहा है। आरोप है कि कुंजबिहारी देर शाम जब रुपये मांगने गए तो अभिषेक पांडेय ने अपने पिता हिमालय पांडेय व 10झ12 अन्य साथियों के साथ मिलकर उन्हें पीटकर घायल कर दिया। परिजन उन्हें उपचार के लिए पहले मेडिकल कॉलेज ले गए। इसके बाद उन्हें राजेंद्रनगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि कुंजबिहारी के सिर की हड्डियां फ्रेक्चर हो गईं और कई नशे क्षतिग्रस्त हो गई थीं। डॉक्टरों ने 24 अगस्त को ऑपरेशन किया था।

सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का आरोप

मृतक के भाई मनोज का आरोप है कि कुंज बिहारी की मौत की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसकी पत्नी रिंकी से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाया। बाद में उसमें यह लिख दिया कि कुंजबिहारी सड़क हादसे में घायल हुआ था। हालांकि पुलिस ने परिजनों को दर्ज केस की कॉपी देते हुए झूठी सूचना होने की बात कही। इसके बाद परिजन लाउडस्पीकर से एनाउंसमेंट करते हुए लोगों से हंगामा न करने की अपील। लेकिन लोग उनकी अपीलों को दरकिनार करते हुए हंगामा करते रहे। मारपीट मामले में कुंज बिहारी ने दो नामजद समेत 12 से अधिक लोगों पर केस दर्ज कराया था। इसमें नामजद अभिषेक पांडेय, उसके पिता हिमालय पांडेय शामिल हैं। इसमें एक आरोपी सहजनवां निवासी अर्जुन को क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ चल रही है।

वरिष्ठ कवि डॉ. 'मानव' को मिला अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय कविता-पुरस्कार

मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, भोपाल ने किया पुरष्कृत

नारनौल। वरिष्ठ कवि डॉ. रामनिवास 'मानव' को मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, भोपाल द्वारा एक लाख का अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय कविता-पुरस्कार (2022) प्रदान किया गया है। अकादमी द्वारा भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक भव्य सम्मान-समारोह में संस्कृति विभाग, मध्यप्रदेश शासन के संचालक एनपी नामदेव, सुप्रसिद्ध उद्घोषक पद्मश्री सुशील दोषी और अकादमी के निदेशक डॉ. विकास दवे ने शॉल, श्रीफल, सम्मान-पत्र और पुरस्कार-राशि का चैक भेंट कर उन्हें पुरस्कृत किया।

उल्लेखनीय है कि डॉ. 'मानव' समकालीन दौर के एक सशक्त क्रांतदर्शी कवि हैं। इनकी विभिन्न विधाओं की चौंसठ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सत्रह काव्य-कृतियाँ शामिल हैं। डॉ. 'मानव' ने काव्य की लगभग एक दर्जन विधाओं में लिखा है, लेकिन इन्हें सर्वाधिक ख्याति दोहाकार के रूप में मिली है। हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, पंचकूला, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर, हिंदी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, हिंदी कल्चरल सोसायटी, टोक्यो (जापान), नेपाल वांग्मय परिषद्, काठमांडू और महाकाली साहित्य संगम, कंचनपुर (नेपाल) सहित देश-विदेश की लगभग डेढ़ सौ प्रमुख संस्थाओं द्वारा पुरष्कृत-सम्मानित डॉ. 'मानव' की विविध रचनाएँ देश के अनेक बोर्डों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। इनकी विविध रचनाएँ विश्व की अनेक प्रमुख भाषाओं में अनूदित चुकी हैं तथा इनके साहित्य पर इक्यावन बार एमफिल, बाईस बार पीएचडी और एक बार डीलिट् हो चुकी है। वर्तमान में सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी (राजस्थान) में प्रोफेसर एवं डीन, कल्चरल अफेयर्स के रूप में कार्यरत डॉ. 'मानव' को इस विशिष्ट उपलब्धि हेतु भारत, नेपाल, यूएई, कतर, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, मॉरिशस, घाना, सूरीनाम, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और बुल्गारिया सहित दो दर्जन देशों के साहित्यकारों और साहित्यानुरागी विद्वानों ने बधाई दी है।

कैदी की मौत : दिनभर बवाल, लाठीचार्ज; विधायक बने मूकदर्शक

औरंगाबाद। औरंगाबाद मंडल कारा के एक बंदी की इलाज के दौरान शनिवार को हुई मौत पर शहर में दिनभर हंगामा होता रहा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब मृतक कैदी के हाथों में मौत के बाद भी हथकड़ी लगी मिली, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोपों को अनसुना करने का विरोध किया और शव को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए ले जाने से रोक दिया। परिजन और ग्रामीण शव को लेकर सदर अस्पताल से रमेश चौक पहुंचे और सड़क को चारों ओर से जाम कर दिया। इससे शहर का यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

मृतक धर्मेंद्र राम, बारूण थाना क्षेत्र के उदीर्ना गांव का निवासी था। परिजनों का आरोप है कि जेल में पुलिस पिटाई के कारण उसकी मौत हुई। उनका कहना है कि धर्मेंद्र पर शराब बेचने का आरोप झूठा था। वह दिल्ली में काम करता था और 15 दिन पहले ही गांव आया था। परिजनों का आरोप है कि साजिशन उसे फंसाकर जेल भेजा गया और वहीं उसकी पिटाई से मौत हुई। धर्मेंद्र के पीछे उसकी पत्नी और दो मासूम बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। परिवार का कहना है कि घर में अब कोई कमाने वाला सदस्य नहीं बचा। धर्मेंद्र की मौत और मौत के बाद भी हथकड़ी नहीं खोले जाने को लेकर ग्रामीण और परिजन रमेश चौक पर जुट गए। जमकर नारेबाजी हुई और जेल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग उठी। सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन उलझ गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने नगर थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह को घेरकर मारपीट की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे अफरातफरी मच गई और कई लोग चोटिल हुए। बाद में वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम हटवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी मिलने पर नबीनगर के राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डबल्यू सिंह भी मौके पर पहुंचे। हालांकि वे स्थिति देखकर मूकदर्शक बने रहे। बाद में उन्होंने कहा कि यह घटना नीतीश सरकार के सुशासन की पोल खोलती है। पहले निर्दोष को झूठे आरोप में जेल भेजा गया और फिर जेल में पिटाई कर मार डाला गया। यदि समय पर कार्रवाई होती तो यह नौबत नहीं आती।

नगर थानाध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि परिजन और ग्रामीण पुलिस से बदसलूकी करने लगे थे, जिसके कारण हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। वहीं एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडेय ने कहा कि उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन हेतु नई 13 सूत्री गाइड लाइन जारी

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मानते हुए आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन हेतु नई 13 सूत्री गाइड लाइन जारी की है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसे सभी नगरीय निकायों में 30 दिनों के भीतर लागू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों के अनुसार अब राज्य में 6 महीने से छोटे कुत्तों की नसबंदी नहीं की जाएगी। इसी तरह दूध पिलाने वाली मादा को तब तक पकड़ने पर रोक रहेगी, जब तक उनके पिल्ले प्राकृतिक रूप से दूध छोड़ न दें।

गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए तार, फंदा या टोंग्स का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल प्रशिक्षित कर्मचारी ही कुत्तों को सुरक्षित जाल या हाथ से पकड़ सकेंगे। प्रत्येक वार्ड में

नसबंदी केंद्रों का नवीनीकरण और नई सुविधाओं जैसे टीकाकरण और डीवार्मिंग की व्यवस्था होगी। कुत्तों को पकड़ने और देखभाल का जिम्मा केवल एडब्ल्यूबीआई से मान्यता प्राप्त एनजीओ को दिया जाएगा, जिन्हें प्रति कुत्ता 200 से 1450 रुपए तक भुगतान होगा। हर नगर निकाय में निगरानी समिति बनाई जाएगी, जिसमें पशु कार्यकर्ता की मौजूदगी अनिवार्य होगी। सभी प्रक्रियाओं की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और 30 दिन का फुटेज रखना होगा। बीमार या घायल कुत्तों का पहले इलाज किया जाएगा, उसके बाद ही नसबंदी होगी। यूडीएच शासन सचिव रवि जैन ने कहा कि यह नीति लोगों की सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को संतुलित करेगी। उल्लंघन करने पर पशु जन्म नियंत्रण नियम 2003 के तहत कार्रवाई होगी। नई गाइड लाइन से राज्य में आवारा कुत्तों के प्रति मानवीय व्यवहार और जनता की सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।

घूँघट की बगावत

31 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

छात्र किस दिशा में जा रहे हैं ?

समाज का दर्पण कहलाने वाला विद्यालय आज एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। जहाँ पहले शिक्षा का अर्थ केवल ज्ञान नहीं बल्कि संस्कार, अनुशासन और नैतिकता था, वहीं अब कुछ घटनाएँ यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि हमारे छात्र आखिर किस दिशा में जा रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के भिवानी जिले के ढाणा लाडनपुर गाँव के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई घटना, जहाँ एक छात्र ने अपने ही शिक्षक पर हमला कर दिया, यह सवाल और गंभीर हो जाता है। यह घटना सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का विवाद नहीं बल्कि पूरे शिक्षा-तंत्र और समाज के लिए चेतावनी है। भारतीय परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी उच्च स्थान दिया गया है झ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः। लेकिन आज की वास्तविकता यह है कि कई जगहों पर शिक्षक-छात्र संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है। पहले शिक्षक की डांट को भी विद्यार्थी प्यार और मार्गदर्शन मानते थे, आज वही डांट अपमान या प्रताड़ना लगती है। मोबाइल और इंटरनेट ने छात्रों को स्वतंत्रता तो दी है, लेकिन साथ ही उनमें अहंकार और अनुशासनहीनता भी बढ़ाई है।

किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व की नींव घर पर रखी जाती है। अगर घर में अनुशासन, संस्कार और मयार्दा का माहौल होगा तो बच्चा वही सीखेगा। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता-पिता बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। टेलीविजन, मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों के 'गुरु' बन गए हैं। नशे और हिंसा जैसी प्रवृत्तियों तक छात्रों की पहुँच आसान हो चुकी है। नतीजा यह कि जब शिक्षक बच्चे को सही राह दिखाने की कोशिश करता है, तो छात्र उसे रोक-टोक या बंधन मानकर विद्रोह कर बैठता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा संकट यह है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी और अंक तक सीमित रह गया है। नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य और चरित्र निर्माण पर जोर लगभग समाप्त हो गया है। बच्चों को 'क्या बनना है' यह तो सिखाया जा रहा है, लेकिन 'कैसा इंसान बनना है' यह कहीं खो गया है। प्रतियोगिता की दौड़ में छात्रों पर दबाव इतना बढ़ गया है कि उनमें सहनशीलता और धैर्य की जगह अधीरता और आक्रामकता ने ले ली है।

आज शिक्षा केवल अंक और नौकरी तक सीमित हो गई है। नैतिक मूल्य और संस्कार बच्चों की प्राथमिकता से गायब होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप २शिक्षक-छात्र संबंधों में खटास बढ़ रही है और अनुशासनहीनता सामने आ रही है। यदि परिवार, समाज, शिक्षक और प्रशासन मिलकर सही कदम नहीं उठाएँगे तो आने वाली पीढ़ी गलत दिशा में बढ़ सकती है। शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और जीवन-मूल्य का आधार बनाना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि हमारे छात्र सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

एक छात्र का अपने शिक्षक पर हमला करना केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि यह पूरी शिक्षा प्रणाली और समाज के लिए शर्मनाक है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। शिक्षक छात्रों को अनुशासित करने से कतराएँगे, विद्यालय की गरिमा को आघात पहुँचेगा और समाज में गलत संदेश जाएगा कि यदि छात्र ही शिक्षक का आदर नहीं करेंगे तो समाज में वरिष्ठों और बड़ों के प्रति सम्मान कैसे बना रहेगा। इस तरह की घटनाएँ केवल विद्यालय स्तर की समस्या नहीं हैं, बल्कि यह कानून-व्यवस्था से भी जुड़ी हैं। ऐसे मामलों में तुरंत और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्र और अभिभावक दोनों यह समझें कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास और परामर्श की भी व्यवस्था हो।

अगर हमें छात्रों को सही दिशा में ले जाना है तो केवल सजा या डर से यह संभव नहीं होगा। इसके लिए बहुआयामी कदम उठाने होंगे। परिवार को बच्चों के साथ संवाद बढ़ाना होगा और घर में अनुशासन और संस्कार का वातावरण बनाना होगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, मूल्य-आधारित शिक्षा और चरित्र निर्माण की गतिविधियाँ अनिवार्य की जानी चाहिए। शिक्षक को भी बच्चों की मानसिकता को समझते हुए संवाद की शैली बदलनी होगी। डांट या डर की बजाय समझाना और विश्वास दिलाना होगा। विद्यालयों में काउंसलिंग कक्ष अनिवार्य होने चाहिए और आक्रामक प्रवृत्ति वाले बच्चों को समय पर मनोवैज्ञानिक सहायता दी जानी चाहिए। समाज और मीडिया को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, हिंसक और नकारात्मक सामग्री के प्रभाव को कम करना होगा और सकारात्मक आदर्श प्रस्तुत करने होंगे।

छात्र किस दिशा में जा रहे हैं? यह सवाल केवल एक घटना से उपजा हुआ प्रश्न नहीं है, बल्कि पूरे समाज की स्थिति पर एक गहरा चिंतन है। यदि आज ही हम बच्चों को अनुशासन, सम्मान और संस्कार की सही राह नहीं दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में शिक्षक-छात्र संबंध और समाज की संरचना दोनों कमजोर हो जाएँगे। समाधान परिवार, विद्यालय, समाज और प्रशासन–सभी के संयुक्त प्रयास में छिपा है। शिक्षा केवल डिग्री दिलाने का माध्यम न होकर चरित्र निर्माण और जीवन मूल्य का संस्कार बने, तभी हम कह पाएंगे कि हमारे छात्र सही दिशा में जा रहे हैं।

डॉ. प्रियंका सौरभ

खिलाड़ी नायिकाएँ: ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ियों का उदय

भारतीय खेल इतिहास लंबे समय तक पुरुष प्रधान रहा, लेकिन बीते कुछ दशकों में महिलाओं ने जिस तरह से अपनी पहचान बनाई है, वह अभूतपूर्व है। कभी खेलों में महिलाओं की भागीदारी सीमित और हाशिए पर थी, परंतु आज भारतीय बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिला खिलाड़ियों का ओलंपिक प्रतिनिधित्व निरंतर बढ़ता गया है। 2000 में नगण्य उपस्थिति से शुरू होकर यह आँकड़ा आज 40झ 44% तक पहुँच चुका है। यह बदलाव केवल खेलों का नहीं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और बदलती सोच का भी प्रतीक है। कहा जाता है–'भर्तृभक्त्या स्त्रियः श्रेयो लभन्ते लोकसम्मतं' अर्थात स्त्रियाँ अपनी निष्ठा और कर्म से लोक में श्रेष्ठ यश प्राप्त करती हैं।

1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में मैरी डिसूजा ने भारत का प्रतिनिधित्व कर इतिहास रचा। वे पहली भारतीय महिला एथलीट थीं जिन्होंने ओलंपिक मंच पर कदम रखा। उस समय न पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएँ थीं, न ही समाज से उन्हें व्यापक स्वीकृति मिलती थी। धीरे-धीरे समय बदला और 1980 के दशक में पी.टी. ऊषा भारतीय खेलों का बड़ा नाम बनीं। 'ट्रैक क्वीन' कही जाने वाली ऊषा ने 1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में 400 मीटर हर्डल्स में चौथा स्थान पाकर इतिहास रचा। पदक से कुछ सेकंड दूर रह जाने पर भी उन्होंने दिखाया कि भारतीय महिलाएँ ट्रैक पर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उनकी उपलब्धि ने असंख्य बेटियों को खेलों की ओर प्रेरित किया। इसके बाद खेलों में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ती गई।

2000 के दशक में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। वे भारत की पहली महिला बनीं जिन्होंने ओलंपिक में पदक हासिल किया। इस उपलब्धि ने महिलाओं की खेल यात्रा में नया साहस और आत्मविश्वास भर दिया। 2010 के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों का स्वर्णिम दौर शुरू हुआ। 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य जीतकर खेल को घर-घर पहुँचाया। उसी वर्ष मणिपुर की मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतकर साबित किया कि साधारण पृष्ठभूमि, माँ और पत्नी होने की जिम्मेदारियों के बावजूद विश्वस्तरीय खिलाड़ी बन सकती हैं। उनका संघर्ष प्रेरणादायक कथा है–साधारण परिवार से निकलकर पाँच बार की विश्व चैंपियन बनीं और राज्यसभा सांसद के रूप में भी सभी को प्रेरणा देती रहीं। 2016 रियो ओलंपिक में भारतीय महिलाओं ने देश की उम्मीदों को संभाला। पी.वी. सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में ह्लप्रोडुनोवाह्व जैसे कठिन वॉल्ट को सफलतापूर्वक कर देश को रोमांचित किया। यहीं से यह धारणा और गहरी हो गई कि महिलाएँ अब हर खेल में समान रूप से आगे बढ़ सकती हैं।

आज भारतीय महिला खिलाड़ी केवल पदक नहीं जीत रहीं, बल्कि रूढ़ियाँ तोड़कर बेटियों को प्रेरित कर रही हैं और यह संदेश दे रही हैं कि खेल जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है–संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि इक्कीसवीं सदी में भारतीय महिलाओं ने खेलों के दिशा और स्वरूप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया।

2020 टोक्यो ओलंपिक (2021) में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीता, लवलीना बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक हासिल किया और पी.वी. सिंधु ने लगातार दूसरी बार पदक जीतकर इतिहास रचा। इन उपलब्धियों का प्रभाव पदकों से कहीं आगे बढ़ा। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियाँ, जहाँ खेलना कभी असंभव माना जाता था, मैरी कॉम, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू को देखकर आगे बढ़ रही हैं। हरियाणा जैसे राज्यों के छोटे गाँवों से निकलकर बेटियाँ अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँच रही हैं, वहीं कभी बेटियों के जन्म पर खुशी तक नहीं मनाई जाती थी। भारतीय महिलाओं का खेल सफर सशक्तिकरण की जीवंत गाथा है। बदलते समाज में परिवार बेटियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्कूल-कॉलेजों में सुविधाएँ बढ़ी हैं और सरकार 'खेलो इंडिया' जैसे कार्यक्रमों से महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर रही है। इस यात्रा से यह सिद्ध होता है कि वास्तविक बदलाव सिर्फ पदकों से नहीं, बल्कि उन संघर्षों से उपजता है जिन्हें खिलाड़ी अपने पीछे प्रेरक उदाहरण के रूप में समाज के लिए छोड़ जाती हैं। पी.टी. ऊषा की दौड़, कर्णम मल्लेश्वरी का ऐतिहासिक पदक, मैरी कॉम की जुझारू लड़ाई, सिंधु का आत्मविश्वास और मीराबाई का साहस–ये सब मिलकर भारतीय महिलाओं की बदलती स्थिति की कथा कहते हैं। जैसा कि मैरी कॉम ने कहा है– कभी हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हार मानते हो, तभी तुम्हारी असली हार होती है।' आज भारतीय महिला खिलाड़ी केवल पदक नहीं जीत रहीं, बल्कि रूढ़ियाँ तोड़कर बेटियों को प्रेरित कर रही हैं और यह संदेश दे रही हैं कि खेल जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है–संघर्ष, अनुशासन और आत्मविश्वास। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह कहा जाएगा कि इक्कीसवीं सदी में भारतीय महिलाओं ने खेलों के दिशा और स्वरूप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया।

डॉ शिवानी कटारा

क्या पशु प्रेम विशेषकर 'कुत्ता प्रेम' को मानव प्रेम पर तरजीह दी जा सकती है ?

इन दिनों भारत में सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवारा कुत्तों को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वैसे तो आवारा कुत्तों के पक्ष में और इसके खिलाफ भारतीय समाज पहले से ही विभाजित है। परन्तु इस विषय को लेकर ताजातरीन बहस की शुरूआत उस समय हुई जब सर्वोच्च न्यायलय ने गत 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर अर्थात दिल्ली, गाजियाबाद , नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में आवारा कुत्तों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुये दिल्ली नगर निगम व अन्य नगर निकायों को निर्देश दिया था कि वे 8 सप्ताह के भीतर सभी आवारा कुत्तों को पकड़ें और उन्हें स्थायी रूप से शेल्टर होम्स या पाउंड्स में रखें। अपने इस आदेश में सर्वोच्च न्यायलय ने कुत्तों को वापस सड़कों पर छोड़ने पर भी रोक लगाई थी । चूँकि कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही थी खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर कुत्तों के हमलों की शिकायतें बढ़ती जा रही थीं और इस संबंध में केवल दिल्ली में ही हजारों मामले दर्ज हो चुके थे और रेबीज से होने वाली मौतें में भी वृद्धि होती जा रही थी इसी के मद्देनजर सर्वोच्च न्यायलय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुये यह आदेश दिए गये थे। अपने आदेश में न्यायलय ने कहा था आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार व नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। इसी के साथ अदालत ने यह निर्देश भी दिया था कि आवारा कुत्तों के लिये शेल्टर होम्स बनाए जाएँ व कुत्तों को पकड़ने के लिए संसाधन भी जुटाये जायें। यहाँ तक कि इस अदालती निर्देश में बाधा डालने वाले पशु प्रेमियों व गैर सरकारी संगठनों को दण्डित करने का भी निर्देश दिया गया था परन्तु इस जनहितकारी अदालती आदेश के बाद तो देश के ह्यकुत्ता प्रेमियोंह्ल में कोहराम मच गया। मानव सुरक्षा को दरकिनार कर ह्यकुत्ता प्रेमियोंह्ल द्वारा तर्क दिया जाने लगा कि शेल्टर होम्स में कुत्ते असुरक्षित रहेंगे। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते लाखों कुत्तों को शेल्टर में रखना अव्यावहारिक है। इससे लाखों कुत्तों को कैद करने और संभावित रूप से मारने का खतरा बढ़ेगा। इसे एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग्स) रूल्स, 2023 का उल्लंघन बताया जाने लगा। पशु प्रेमियों द्वारा इस अदालती आदेश को 'बहुत कठोर' बताया जाने लगा। जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो गये। कुत्ता प्रेमी अदालती आदेश की अवहेलना करने पर आमादा दिखाई देने लगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर 22 अगस्त 2025 को एक संश-ोधित आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 11 अगस्त 2025 के मूल आदेश में बदलाव करते हुये नये निर्देश जारी किये। इन संश-ोधित निदेर्शों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि कुत्तों को पकड़ना जारी रखें, लेकिन उन्हें स्टरलाइज (नसबंदी), डीवार्म (कीड़े निकालना) तथा वैक्सीनेट (टीका लगाना) करें गैर -आक्रामक (नॉन-एग्रेसिव) और गैर-संक्रमित (रेबीज मुक्त) कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ें। केवल रेबीज संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को ही अलग शेल्टर में रखें। जबकि सड़कों पर खाना खिलाना प्रतिबंधित करार दिया गया। अदालत ने प्रत्येक वार्ड में समर्पित फीडिंग स्पॉट बनाने व नोटिस बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया। यह भी निर्देशित किया गया कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकते। इन निदेर्शों में बाधा डालने वाले कथित 'पशु प्रेमियों' पर व्यक्तिगत तौर पर 25,000 तथा गैर सरकारी संगठनों पर 2,00,000 रुपए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया गया। जुर्माने से वसूली गई यह धनराशि शेल्टर होम बनाने में इस्तेमाल होगी। यह संशोधित आदेश पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और एबीसी रूल्स, 2023 पर आधारित है, जो पशुओं को मारने के बजाय स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन पर जोर देता हैं परन्तु समाज के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि नागरिक सुरक्षा और पशु कल्याण के मध्य संतुलन कैसे बिठाया जाये। पशु प्रेमी होने में कोई बुराई नहीं। परन्तु क्या पशु प्रेम विशेषकर 'कुत्ता प्रेम' को मानव प्रेम पर तरजीह दी जा सकती है ? देश में रोजाना कुत्ते के काटने से सैकड़ों लोग बुरी तरह घायल होते हैं। अनेक की मौत हो जाती है। इनहीं कुत्तों की वजह से अनेक दुर्घटनायें होती हैं। स्कूल जाते बच्चों पर व असहाय बुजुर्गों पर आवारा कुत्ते घातक हमले कर देते हैं। उस समय इन कुत्तों से प्यार करने वाला कोई भी पशु प्रेमी सामने नहीं आता। उल्टे कई बार तो पीड़ित राहगीरों पर ही यह दोष मढ़ दिया जाता है कि वह उधर से गुजरा ही क्यों ? या फिर पहले उसने कुत्ते को छेड़ा होगा आदि आदि। हद तो यह है कि कई बार यही कुत्ते अपने ह्यकुत्ता प्रेमी ह्य को ही काट लेते हैं। निश्चित रूप से कुत्तों को दोष इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उनकी प्रवृति ही हिंसक है। इसलिये कुत्तों के काटने भोंकने या उनके पीछे दौड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कुत्तों की वफादारी से भी इंकार नहीं किया जा सकता। कुत्तों को तो मनुष्य से भी अधिक वफादार माना जाता है। परन्तु उनकी हिंसक प्रवृत्ति को नकारना और कुत्ता प्रेम की शर्त पर मानव सुरक्षा से समझौता करना भी तक-संगत नहीं। इसी संदर्भ में एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जिस तरह सर्वोच्च न्यायलय के गत 11 अगस्त के आदेश के बाद देश के कुत्ता प्रेमी सड़कों पर उतर आये और अपने पशु प्रेमी होने का प्रदर्शन करने लगे यहाँ तक कि कई कुत्ता प्रेमी तो अदालती आदेश को लेकर रोते पीटते भी दिखाई दिये वास्तव में यदि इसी स्तर पर समग्र भारतीय समाज में मानव प्रेम की भावना होती तो शायद आज देश में कहीं भी वृद्धाश्रम की जरुरत न होती। वृंदावन में लाखों विधवाएं अपने भाग्य पर आंसू न बहा रही होतीं। अयोध्या,मथुरा व काशी जैसे अनेक धर्म स्थान बुजुर्ग व असहाय भिखारियों से भरे न होते। देश के स्टेशन व फुट पाथ पर बड़ी संख्या में निराश्रित लोग नजर न आते। यानी पशु प्रेमियों के इस देश में कम से कम वृद्ध जनों की ऐसी दुर्दशा देखने को तो न मिलती?

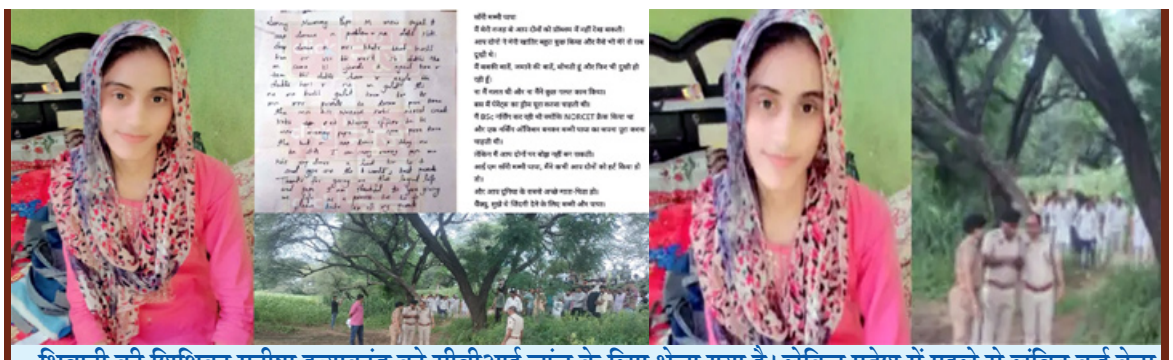

भिवानी की शिक्षिका मनीषा हत्याकांड को सीबीआई जांच के लिए भेजा गया है। लेकिन प्रदेश में पहले से लंबित कई केस यह सवाल खड़े करते हैं कि क्या सीबीआई जांच से न्याय मिलेगा? 1995 की छात्रा हत्या का आरोपी 30 साल से फरार है, 2013 का पूर्व जज द्वारा पत्नी हत्या केस 12 साल से कोर्ट में लंबित है, 2017 का छात्र हत्या और 2022 का सोनाली केस भी अब तक अधर में हैं। न्याय में ऐसी देरी पीड़ित परिवार को तोड़ देती है और समाज के भरोसे को कमजोर करती है। अब जरूरत है फास्ट ट्रैक कोर्ट, समयसीमा तय जांच और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया की।

न्याय की देरी: व्यवस्था पर सवाल

हरियाणा के भिवानी की शिक्षिका मनीषा की हत्या ने न केवल एक परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि समाज को भी झकझोर कर रख दिया है। यह घटना फिर से उस गहरे सवाल को सामने लाती है जो वर्षों से हमारे न्याय तंत्र पर मंडराता आ रहा है–क्या हमारे देश में समय पर न्याय मिल पाना संभव है?

मनीषा का मामला अब सीबीआई के पास भेजने की प्रक्रिया में है। पुलिस ने मुख्यालय को पत्र लिख दिया है और उम्मीद जगाई जा रही है कि सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या यह मान लेना चाहिए कि सीबीआई जांच ही न्याय की गारंटी है? अतीत के कई मामलों को देखें तो जवाब निराशाजनक मिलता है। हरियाणा और आसपास के जिलों के कई ऐसे बड़े केस हैं जिन्हें सालों पहले सीबीआई को सौंपा गया, लेकिन आज भी वे न्याय की मंज़िल तक नहीं पहुंचे। 1995 में 11वीं कक्षा की छात्रा की हत्या हुई थी, आरोपी 30 साल से फरार है। यह केवल पीड़िता के परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है। 2013 में पूर्व जज द्वारा पत्नी की हत्या का मामला पिछले 12 साल से कोर्ट में लंबित है। आरोपी को 2016 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल आज भी अधूरा है। 2017 में छात्र की हत्या के मामले में सीबीआई ने स्कूल के ही छात्र को आरोपी बनाया था। आठ साल हो चुके हैं, पर केस का कोई अंतिम नतीजा सामने नहीं आया। 2022 का सोनाली हत्या कांड भी तीन साल बाद अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या क्यों हुई। इसी तरह प्रेम विवाह पर युवक की हत्या का केस 2015 से कोर्ट में चल रहा है और आठ साल बाद भी फैसला नहीं आया।

इन उदाहरणों से साफ है कि सीबीआई को केस सौंप देना न्याय का पर्याय नहीं है। कई बार तो यह केसों को और ज्यादा लंबा कर देता है। न्याय में देरी केवल कानूनी औपचारिकता नहीं है, यह सीधे-सीधे पीड़ित परिवार पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बोझ डालती है। हर सुनवाई पर परिवार के सदस्य उम्मीद लेकर कोर्ट जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज कोई ठोस कदम उठेगा। लेकिन बार-बार अगली तारीख मिलती है। यह सिलसिला महीनों नहीं, बल्कि वर्षों तक चलता रहता है। ऐसे में पीड़ित परिवार की हिम्मत टूट जाती है। कई बार गवाह समय के साथ कमजोर हो जाते हैं या डर के कारण पलट जाते हैं। सबूत समय बीतने के साथ कमजोर पड़ जाते हैं। आरोपी खुलेआम समाज में घूमते रहते हैं और पीड़ित परिवार यह सोचता रह जाता है कि कानून आखिर किसके लिए बना है। देरी की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि फरार आरोपियों को पक-ड़कर कोर्ट के सामने पेश करे। लेकिन कई मामलों में आरोपी वर्षों तक फरार रहते हैं और पुलिस केवल बयान देती रह जाती है। सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां अक्सर केस की जांच लंबी खींच देती हैं। रिपोर्ट्स तैयार करने में वर्षों लग जाते हैं और कभी-कभी राजनीतिक दबाव भी जांच की दिशा बदल देता है। न्यायपालिका में केसों की संख्या इतनी अधिक है कि हर सुनवाई महीनों बाद मिलती है। ट्रायल की प्रक्रिया धीमी है, और फैसला आने में दशकों लग जाते हैं। सरकार की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर न्यायिक ढांचे को पर्याप्त संसाधन और आधुनिक तकनीक नहीं दी जाएगी तो देरी होना तय है। जब अपराधी खुले घूमते हैं और पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर लगाता रहता है, तो समाज का भरोसा कानून से उठने लगता है। लोग धीरे-धीरे यह सोचने लगते हैं कि न्याय मिल ही नहीं सकता। कुछ मामलों में परिवार या समाज खुद बदला लेने की कोशिश करता है। यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, क्यों-कि न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठना, अराजकता की शुरूआत है।

अगर हम वास्तव में यह चाहते हैं कि मनीषा और उसके जैसी बेटियों को न्याय मिले, तो इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जघन्य अपराधों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं ताकि सुनवाई समयबद्ध हो। सीबीआई जांच के लिए समयसीमा तय की जाए। केस सौंपते समय यह सुनिश्चित हो कि छह महीने या एक साल में रिपोर्ट आनी ही चाहिए। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। हर छह महीने में पीड़ित परिवार को केस की स्थिति बताई जाए। अदालतों और जांच एजेंसियों में डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम हो ताकि देरी का कारण साफ दिखाई दे। गवाह संरक्षण योजना को सख्ती से लागू किया जाए ताकि गवाह डर के कारण पलट न सकें।

मनीषा की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है। यह हमारे समाज की उस विफलता की कहानी है जहां बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं और अगर उनके साथ कुछ हो भी जाए तो न्याय पाने में वर्षों लग जाते हैं। मनीषा का परिवार आज भी उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन उनकी उम्मीद तभी साकार होगी जब यह केस समय पर निपटे। अगर यह भी अन्य मामलों की तरह वर्षों तक खिंच गया, तो समाज का भरोसा और कमजोर होगा। न्याय में देरी का मतलब है न्याय से इनकार। जब आरोपी सालों तक सजा से बच जाते हैं, तो यह संदेश जाता है कि कानून शक्तिशाली के लिए ढीला और कमजोर के लिए सख्त है। मनीषा और उससे पहले की कई बेटियाँ आज भी इंसाफ की आस लगाए बैठी हैं। उनकी आंखों से टपकता दर्द हम सबकी सामूहिक नाकामी है। अब समय आ गया है कि सरकार, न्यायपालिका और जांच एजेंसियां मिलकर यह सुनिश्चित करें कि न्याय केवल मिलेगा ही नहीं, बल्कि समय पर मिलेगा।

– डॉ. सत्यवान सौरभ

आत्म निर्भर भारत में महिला श्रम की उल्लेखनीय भागीदारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत की बात की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर उन्होंने कहा, एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है, तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए, बनाए और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।

आत्मनिर्भरता भारत की संकल्पना ही नहीं, अपितु वह सत्य है, जो आत्मबल की कथा लिखती है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका अपेक्षित ही नहीं, अपरिहार्य भी है। नारी शक्ति अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अभियान बनना चाहिए। विगत एक दशक में महिलाएं केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भागीदार भी बन चुकी हैं। देश की आधी आबादी का सशक्तीकरण अब सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि विकास की रणनीति बनने को है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 ने भारत में महिला श्रम भागीदारी दर में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर किया, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि के कारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में मुद्रा योजना से बदलते आर्थिक परिदृश्य और महिलाओं के सशक्तीकरण में उसकी अहम भूमिका की चर्चा की। मुद्रा योजना के कुल लाभार्थियों में 68 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो देश भर में महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2016 और वित्त वर्ष 2025 के बीच प्रति महिला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वितरण राशि 13 प्रतिशत से बढ़कर 62,679 रुपये तक पहुंच गई, जबकि प्रति महिला वृद्धिशील जमा राशि वर्ष दर वर्ष 14 प्रतिशत बढ़कर 95,269 रुपए हो गई। ऋण वितरण में महिलाओं की अत्यधिक हिस्सेदारी वाले राज्यों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले एमएसएमई के माध्यम से काफी अधिक रोजगार सृजन किया है, जो महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में लक्षित वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह योजना महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्त तक पहुंच प्रदान करने में सहायक रही है। आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव के शिल्पकार 'महिला स्वयं सहायता समूह' भी हैं, जिनकी प्रधानमंत्री ने लाल किले से प्रशंसा करते हुए कहा, पिछले 10 साल में वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कमाल करके दिखाया है। आज उनके प्रोडक्ट दुनिया के बाजार में जाने लगे हैं। स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत का नवीन कथानक लिख रहे हैं। 31 जनवरी, 2025 तक लगभग 10.05 करोड़ महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूह आमतौर पर समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 10-12 महिलाओं का एक समुदाय होता है। एसएचजी से जुड़ी महिलाएं संयुक्त आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को एकत्रित करने या सदस्यों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण देने के लिए संगठन बनाती हैं। भारत के स्वयं सहायता समूहों को सामूहिक रूप से दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस परियोजना माना जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार स्वयं सहायता समूह की बैंक पुनर्भुगतान दर 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री ने 'नमो ड्रोन दीदी नारी शक्ति योजना' का भी उल्लेख किया। 15 अगस्त, 2023 को प्रारंभ की गई नमो ड्रोन दीदी योजना स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि में ड्रोन के उपयोग के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी (आठ लाख रुपये तक) और प्रशिक्षण प्रदान करके सशक्त बनाती है, जिससे उनकी आय सालाना एक लाख रुपये से अधिक तक बढ़ जाती है, टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलता है और ग्रामीण रोजगार एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलता है। इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-2026 की अवधि के दौरान 15,000 चुनिंदा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करना है, ताकि कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान की जा सकें। लीक से हटकर करने की चाह को जब सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन प्राप्त हो तो महिलाओं को सशक्त और संबल होने से कोई नहीं रोक सकता। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत देश भर में महिला सशक्तीकरण परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत महिला किसानों को कृषि के आधुनिक तौर-तरीके सिखाए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों की परिणति 'देसी कोल्ड स्टोर' है, जो झारखंड की महिला किसान बांस से बना रही हैं।

दादा गौतम उर्फ.हरियाणा के विधायक रामकुमार गौतम द्वारा विधानसभा में उठाया गया मुद्दा केवल विवाह की सहमति भर का नहीं, बल्कि समाज की दिशा और संस्कृति के संरक्षण का संकेत है। अभिभावकों की सहमति से विवाह संस्था मजबूत रहती है, जबकि युवाओं की स्वतंत्रता से समाज प्रगतिशील बनता है। चुनौती यह है कि दोनों के बीच संतुलन कायम किया जाए। कानून से अधिक आवश्यक है संवाद और परामर्श की संस्कृति। परिवार और बच्चों का पारस्परिक सम्मान ही वह आधार है, जो विवाह संस्था की गरिमा और समाज की नैतिकता को बनाए रख सकता है।

जवान बच्चों की शादी में अभिभावकों की सहमति : परंपरा, अधिकार और सामाजिक संतुलन

भारत जैसे सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों वाले देश में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी निर्णय नहीं होता, बल्कि यह परिवार, रिश्तेदार और व्यापक समाज की भागीदारी से जुड़ी एक सामाजिक संस्था है। ऐसे में जब हरियाणा विधानसभा में दादा गौतम ने यह मुद्दा उठाया कि जवान बच्चों की शादी में माँ-बाप की सहमति अनिवार्य होनी चाहिए, तो इस पर स्वाभाविक रूप से बहस छिड़ गई। यह बहस केवल एक कानूनी प्रावधान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में हैं—नैतिकता, परंपरा, संस्कृति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा।

भारतीय संस्कृति में विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध या कानूनी व्यवस्था नहीं, बल्कि संस्कार है। विवाह को परिवारों का मिलन माना जाता है, न कि केवल दो व्यक्तियों का। यही कारण है कि भारत में अधिकांश विवाह आज भी परिवार और समाज की सहमति से ही तय होते हैं। माता-पिता अपने बच्चों के विवाह में केवल निर्णयकर्ता नहीं, बल्कि मार्गदर्शक होते हैं। उनका अनुभव, सामाजिक पहचान और रिश्तों की समझ विवाह संस्था को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। परंपरा का यह स्वरूप परिवार की इज्जत-आबरू, सामाजिक प्रतिष्ठा और रिश्तों की निरंतरता से गहराई से जुड़ा हुआ है। विधानसभा में उठाया गया यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक समय में तेजी से बदलती जीवनशैली और युवाओं की बढ़ती स्वतंत्रता ने विवाह संस्था की परिभाषा को बदलना शुरू कर दिया है। कई युवा प्रेम विवाह को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिवार की सहमति के बिना विवाह करने के मामलों में वृद्धि हो रही है। कई बार ये विवाह सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और पारिवारिक दबाव के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में सामने आते हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि यदि हर विवाह केवल व्यक्तिगत निर्णय बन जाए और अभिभावकों की सहमति को दरकिनार कर दिया जाए, तो समाज में नैतिकता, संस्कृति और रिश्तों की गरिमा पर गहरा संकट खड़ा हो सकता है। अभिभावकों की सहमति के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह है कि यह परिवार की इज्जत और सामाजिक आबरू को बनाए रखती है। माता-पिता का अनुभव बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता है। जीवन की कठिनाइयों, रिश्तों की बारीकियों और सामाजिक जिम्मेदारियों की समझ उनसे बेहतर किसी को नहीं हो सकती। विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि परिवारों और संस्कृतियों का मिलन होता है, इसलिए अभिभावकों की सहमति से विवाह में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की संभावना अधिक होती है। जब परिवार पीछे खड़ा होता है तो विवाह का भावनात्मक संतुलन भी मजबूत रहता है।

दूसरी ओर विपक्ष में यह तर्क भी उतना ही प्रबल है कि भारतीय संविधान हर वयस्क नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का जीवनसाथी चुन सके। किसी भी प्रकार से अभिभावक की सहमति को बाध्यकारी बनाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन होगा। कई बार अभिभावक जाति, धर्म, वर्ग या आर्थिक स्थिति को प्राथमिकता देकर बच्चों की पसंद को नकार देते हैं। ऐसे में यदि उनकी सहमति अनिवार्य कर दी जाए तो यह समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। अनचाहे विवाह का खतरा भी इसी से पैदा होता है, जहाँ बच्चों पर दबाव डालकर उनकी पसंद के विरुद्ध विवाह कराए जाते हैं। इससे न केवल विवाह असफल होते हैं बल्कि समाज में असंतोष और तनाव भी बढ़ता है। युवाओं की स्वतंत्रता और समाज की प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपनी पसंद के निर्णय लेने का अवसर मिले। समाज तभी प्रगतिशील बन सकता है जब जातिगत और परंपरागत बंधनों को तोड़कर समानता और आधुनिकता को अपनाया जाए। यह भी सच है कि हर अभिभावक आवश्यक नहीं कि समझदार और प्रगतिशील हो। कई बार उनकी सोच परंपराओं और रूढ़ियों से बंधी होती है, जो बच्चों की स्वतंत्रता और खुशी के आड़े आ सकती है।

स्पष्ट है कि दोनों पक्षों में ठोस तर्क हैं। अभिभावकों की सहमति पूरी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि यह परिवार और समाज के लिए आवश्यक है। वहीं युवाओं की स्वतंत्रता भी कमतर नहीं आँकी जा सकती, क्योंकि यह उनका संवैधानिक अधिकार है। अतः समाधान इस टकराव में नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद में है। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की भावनाओं, पसंद और स्वतंत्रता को समझें। युवाओं को चाहिए कि वे अपने निर्णय में परिवार की प्रतिष्ठा और अनुभव को महत्व दें। सरकार और समाज की भूमिका यह होनी चाहिए कि वे संवाद और परामर्श को बढ़ावा दें, न कि केवल कानून बनाकर किसी एक पक्ष को बाध्य करें। यदि सरकार इस विषय पर कदम उठाना चाहती है, तो सीधे कानून बनाने की बजाय कुछ सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। विवाह के विवादित मामलों में परिवार और युवाओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए परामर्श केंद्र बनाए जा सकते हैं। जल्दबाजी और भावनात्मक निर्णयों को संतुलित करने के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक काउंसलिंग की व्यवस्था हो सकती है। अभिभावकों को समझाने के लिए संवेदनशीलता अभियान चलाए जा सकते हैं कि बच्चों की पसंद को नकारना समाधान नहीं है। वहीं युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम जरूरी हैं ताकि वे विवाह को केवल भावनात्मक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझें।

दादा गौतम द्वारा उठाई गई चिंता समाज के लिए एक आवश्यक चेतावनी है। अगर विवाह संस्था से परिवार और अभिभावकों की भूमिका पूरी तरह हटा दी गई, तो समाज में नैतिकता और संस्कार कमजोर होंगे। वहीं अगर अभिभावकों की सहमति को कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया, तो युवाओं की स्वतंत्रता पर चोट पहुँचेगी। इसलिए समाधान केवल यही है कि विवाह संस्था को संवाद, सहमति और समझदारी पर आधारित बनाया जाए। अभिभावकों और बच्चों के बीच पारस्परिक सम्मान ही वह पुल है, जो परंपरा और आधुनिकता, अधिकार और जिम्मेदारी, स्वतंत्रता और संस्कार के बीच संतुलन स्थापित कर सकता है। यदि हम इस संतुलन को साध सके, तभी विवाह संस्था अपनी वास्तविक गरिमा और पवित्रता बनाए रख सकेगी और आने वाली पीढ़ियाँ एक सशक्त, संस्कारित और स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकेंगी।

डॉ. प्रियंका 'सौरभ'

ज्वलनशील मुद्दा : दहेज उत्पीड़न कानून का दुरुपयोग

दहेज उत्पीड़न के मामले से देश में आते रहते है लेकिन इस के फलस्वरूप हत्या जैसे मामले ज्यादातर उत्तर भारत में आते हैं। दहेज को लेकर देश के अन्दर इतना कठोर कानून है कि उत्पीड़न का मामला होने मात्र से ही पूरा परिवार जेल के अन्दर सड़ता रहता है। जबकि यदि हत्या आत्मा को छोड़ दिया ये अधिकांश मामले जो दहेज उत्पीड़न के लिये जाते है उनके पीछे दूसरे बहुत से कारण होते हैं। ज ही एकमात्र ऐस 'कानून होता है जिसमें पूरे परिवार को बिना सजा के ही मिल जाती है इसलिए यह कहा जाता है कि इस कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली नी नामक एक महिला की ज्वलनशील पदार्थ चलकर हत्या कर दी गयी जिसका न सिर्फ बीडियो सामने आया बल्कि निक्की का छोटा बच्चा भी बता रहा है कि पापा ने कैसे मां को मारा और लाइटर से आग लगा दी। ज्वलनशील पदार्थ सम्भवतः पेट्रोल था जिसकी वजह से मिकी की जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद उसके पति को पुलिस ने हाफ इनकाउंटर करके गिरफ्तार किया और पूरे परिवार को जेल के सीखचों में डाल दिया है। निकी की बहन कंचन भी उसी घर में है उसका भी आरोप है कि उसकी बहन के पति और ससुर ने ही निशी को मारा है। मिश्री की शादी नौ साल पहले हुई थी और उसके पिता का आरोप है कि ससुराल वाले 36 लाख नकद और एक महंगी कार की मांग में की पर शारीरिक अत्याचार करते थे और आखिर दहेज का कानून इतना पुराना तो हो ही चुका है कि उसकी स्थिति से सभी वाकिफ से चुके हैं कि यदि उन्होंने कोई घटना की उनका क्या होगा। बहुत से लोग इस इन्तजार में रहते हैं कि किसी तरह से शादी के दस साल निकल जाये जिससे वह दहेज कानून की प्रताड़ना से बाहर आ सके इस कानून को लेकर भय भी है। दहेज के नाम पर होने वाली मौते या हत्याएं समाम कानूनों के बावजूद अब तक इस सामाजिक कलंक से निजात नहीं दिला सकी है। दहेज का वजूद दिनों दिन बड़ा ही जा रहा है। क्योंकि समाज में झूठी शान, प्रतिष्ठ धन का प्रतीक बनी हुई है और लड़कियों का महत्व आज भी यह नहीं है जो लड़कों का है। संविधान और तमाम कानून भले ही उसे बराबरी का दर्जा देते हो लेकिन लड़की अभी भी दोयम दर्जे की ही है। जिस दिन लड़की दोयम दर्जे की नहीं रह जायेगी दहेज का यह भस्मासुर भी खत्म हो जायेगा।

हिन्दी शिक्षकों की कमी : शिक्षा की आत्मा पर संकट

हरियाणा के विद्यालयों में अध्यापकों के सोलह हजार आठ सौ चालीस पद रिक्त हैं, जिनमें सर्वाधिक कमी हिन्दी विषय की है। हिन्दी केवल एक विषय नहीं बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा की आत्मा है। भाषा की कमजोरी से गणित, विज्ञान और अन्य विषयों की समझ भी प्रभावित होती है। सरकार ने अस्थायी नियुक्तियाँ तो की हैं, पर स्थायी भर्ती की गति धीमी है। यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो शिक्षा का स्तर गिरने के साथ-साथ सांस्कृतिक जड़ों से भी दूरी बढ़ेगी।

हरियाणा विधानसभा में हाल ही में प्रस्तुत आँकड़े यह चौंकाने वाले तथ्य सामने लाते हैं कि प्रदेश के चौदह हजार दो सौ पचानवे विद्यालयों में से सोलह हजार आठ सौ चालीस पद अध्यापकों के रिक्त पड़े हैं। यह केवल संख्या नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की गहरी चिन्ता का विषय है। और सबसे अधिक चिन्ताजनक तथ्य यह है कि इन रिक्तियों में सर्वाधिक पद हिन्दी विषय के अध्यापकों के हैं।

हिन्दी केवल एक विषय नहीं, बल्कि सम्पूर्ण शिक्षा का आधार है। भाषा वह माध्यम है, जिसके जरिये बालक अन्य सभी विषयों को समझता है। यदि भाषा में पकड़ नहीं होगी तो गणित के सूत्र, विज्ञान के सिद्धान्त और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी अधूरे रहेंगे। इसीलिये हिन्दी अध्यापकों की भारी कमी केवल भाषा शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तन्त्र की कमजोरी का संकेत है।

किसी भी समाज की शिक्षा व्यवस्था उसकी मातृभाषा पर आधारित होती है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में हिन्दी करोड़ों लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। हरियाणा जैसे हिन्दीभाषी राज्य में बच्चों के लिये पहली शिक्षा हिन्दी के माध्यम से ही होती है। यदि हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापक ही पर्याप्त नहीं होंगे, तो बच्चे न केवल भाषा में पिछड़ेंगे बल्कि अन्य विषयों को भी सही ढंग से आत्मसात नहीं कर पाएँगे। आज स्थिति यह है कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक हजारों पद खाली पड़े हैं। हिन्दी की कक्षाएँ कई स्थानों पर या तो बिना अध्यापक के चल रही हैं या फिर अस्थायी अध्यापकों के भरोसे हैं। इसका सीधा प्रभाव बच्चों की लिखने-पढ़ने की क्षमता पर पड़ रहा है। बच्चे शब्दों का सही उच्चारण, वाक्य निर्माण और व्याकरण में दक्ष नहीं हो पा रहे हैं। जब भाषा में पकड़ कमजोर होगी तो गणित, विज्ञान या इतिहास पढ़ते समय भी विद्यार्थी समझ नहीं पाएँगे। आज प्रत्येक परीक्षा में हिन्दी अनिवार्य है। अध्यापक की कमी से विद्यार्थियों की तैयारी अधूरी रह जाती है। भाषा केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, संस्कृति का वाहक भी है। हिन्दी से दूरी का अर्थ है अपनी जड़ों से दूरी। हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब तक एक लाख उन्तीस हजार चार सौ तीस नियुक्तियाँ की हैं। इसमें आरक्षण और कोटा भी लागू किया गया है। किन्तु यह नियुक्तियाँ अधिकतर अस्थायी हैं। स्थायी भर्ती की गति अत्यन्त धीमी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दो हजार आठ सौ छप्पन पद रिक्त हैं। सहायकों के चार हजार आठ सौ नौ पद खाली हैं। स्नातकोत्तर अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक और प्राथमिक स्तर पर भी हजारों पद खाली हैं। हिन्दी विषय में रिक्तियों की संख्या सबसे अधिक है।

सरकार के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जारी है, किन्तु अस्पष्ट नीतियों, आरक्षण विवाद, और प्रशासनिक विलम्ब के कारण बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब, निजीकरण का दबाव, सामाजिक मानसिकता और नीति-निर्माण में लापरवाही ने इस समस्या को और गम्भीर बना दिया है। विज्ञान और गणित को प्राथमिकता देते हुए हिन्दी को सहायक विषय की तरह देखा गया, जबकि यह शिक्षा की आत्मा है।

इस समस्या का समाधान केवल संख्यात्मक नियुक्तियों से नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण भर्ती और प्रशिक्षण से ही सम्भव है। रिक्त पड़े हिन्दी अध्यापकों के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। अस्थायी व्यवस्था से शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। स्थायी अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य है। केवल नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं, अध्यापकों को समय-समय पर आधुनिक पद्धतियों और तकनीक का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। हिन्दी विषय को ह्यकम महत्त्वपूर्णह्न मानने की मानसिकता बदली जानी चाहिए और ग्रामीण-शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से नियुक्ति होनी चाहिए।

आज जब भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना लेकर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, तब हिन्दी की महत्ता और भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक वैश्विक मंचों पर हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में यदि हमारे ही बच्चों को हिन्दी का बुनियादी ज्ञान नहीं मिलेगा तो यह विडम्बना ही होगी। हिन्दी केवल भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। इसे सुदृढ़ करना अर्थात् पूरे शिक्षा तन्त्र को सुदृढ़ करना है। यदि हम बच्चों को हिन्दी में सक्षम बनाएँगे तो वे अन्य सभी विषयों में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएँगे। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में सोलह हजार आठ सौ चालीस रिक्त पद केवल प्रशासनिक आँकड़ा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की चिन्ता है। और हिन्दी विषय में सबसे अधिक कमी होना इस चिन्ता को और गहरा बना देता है। सरकार को चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया को तीव्र करे, स्थायी नियुक्तियाँ सुनिश्चित करे और भाषा शिक्षा को प्राथमिकता दे। यदि हिन्दी अध्यापकों की कमी पूरी नहीं की गई तो यह केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का भी नुकसान होगा। हमें यह समझना होगा कि भाषा ही शिक्षा की आत्मा है। आत्मा के बिना शरीर जितना निष्प्राण होता है, शिक्षा भी भाषा के बिना उतनी ही निर्जीव है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

व्यंग्य

पत्रकारिता में भी जाति का बोलबाला आवास ना देने वाली सरकार का मुंहकाला

अगस्त माह में लखनऊ के एक हाल में क्षत्रिय पत्रकार मिलन समारोह देख कर मन दहाड़ उठा। अब भरोसा होने लगा कि यूपी में ठाकुरों की सरकार ही है तभी तिवारी जी, शर्मा जी और अवस्थी जी विधानसभा में मिल तो गये पर हाथ केवल कैमरा लिए, उधर पता चला रिटायर होने के बाद भी बड़का पत्रकार अवस्थी जी जोश में थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकारी आवास एवं सारी सुविधायें तो नहीं मिली पर विधानसभा का पास मंत्री जी की कृपा से कई बार मिला है। मैंने पूछा मंत्री जी आपका नाम जानते होंगे वो पलटकर बोले, हाँ। उन्होंने अग्निहोत्री की इशारा किया और अग्निहोत्री जी, मिश्रा जी और शुक्ला जी से भी हामी भरवायी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। तभी उपाध्याय जी मिल गये, और उन्होंने कहा कि ठाकुरों की ही सरकार है तो मैंने फिर जोश में आकर काशी में पत्रकार आवास आवंटन और पत्रकार पेंशन का फार्म भर दिया मैंने भी। फिर पांच साल से लगातार फार्म भरने के बाद अब मैं भी मानने लगा कि यह ठाकुरों की ही सरकार है। फार्म भरते समय ही वरिष्ठ युवा पत्रकार तिवारी जी रोड साइड रोमियो बने टहलते मिल गये। उन्होंने बताया कि अब भी यह पिछड़े, दलित, यादवों और मुस्लिमों की ही सरकार है, इसमें सरकारी आवास मिलना मुश्किल है। हमारा दिल टूट गया। अब भरे थे, तो वापस नहीं लिये, क्या पता यादव-मुस्लिमों की सरकार किसी मिशिर को भी सरकारी आवास आवंटित कर दे। परंतु ऐसा हो ना सका, पिछड़े यादव और मुसलमानों की सरकार ने तिवारी जी और शकील भाई को सरकारी आवास आवंटित किया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। किसी यादव का भी नहीं हुआ, क्योंकि शायद सरकार उनको जानती नहीं थी। महीने बीत गये। हमारी उम्मीद टूटने लगी। पर यादव जी, श्रीवास्तव जी, शर्मा जी, मिश्रा जी, पाठक जी, शुक्ला जी जब भी मिलते और कहते कि ठाकुरों की सरकार है तो उम्मीद फिर से जग जाती। इंतजार करते करते मीटिंग हो ही गई। दीक्षित जी, वाजपेयी जी, शुक्ला जी, सेंगर जी, सिंह जी को आवास आवंटन हो गया, लेकिन हमारा होइबे नहीं किया। फिर हमको अपने मिश्रा होने पर ही शक होने लगा।

इसी उधेड़बुन में गांव पर पता कराया तो मालूम हुआ कि हम लोग पहिले जजमनिया पत्रकार थे इसलिए लोचा है, मुझे लगा मेरी शक्ल की वजह से शायद सरकार मुझे वरिष्ठ पत्रकार नहीं मान रही है तो सर्टिफिकेट ही बनवा लेते हैं, लेकिन वो भी नहीं बन पाया। फिर पाठक जी ने बताया कि यह ठाकुरों की सरकार है तो मेरा भरोसा फिर मजबूत हुआ। खैर, तिवारी जी जब मिलते तब यही बताते कि यादवों-मुसमलमानों की सरकार है, सरकारी आवास आवंटन मुश्किल है। यह भी बताते कि उन्होंने अपने लॉन में सब्जी बो दिया है, लेकिन यह सरकार यादवों-मुसलमानों की है। हमने दुखी होकर आवास आवंटन का फार्म भरना ही छोड़ दिया। समय बीतता गया। 2017 में भाजपा की सरकार आ गई। एक संन्यासी गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाये गये। उनसे परिचय नहीं होने के चलते मैंने आवास आवंटन के लिये फार्म नहीं भरा। समय बीतता रहा। गंगा में पानी बहता रहा। इसी बीच शुक्ला जी के सूत्र ने बताया कि ठाकुरों की सरकार है और मेरा आवेदन ऊपर तक पहुंच गया है। मैं खट से घुंघारी बाबा को सवा किलो लड्डू मान दिया। इस उम्मीद में कि क्या पता ब्रह्म बाबा डेढ़ पाव लड्डू की वजह से ही आवंटन नहीं करा रहे हों। फिर शुक्लाजी के सूत्र ने मुझे बताया कि मामला तो ठाकुर होने तक पहुंच गया था, लेकिन जायसवाल जी ने इसलिये रोक लिया कि हम औचित्यहीन और किसी काम के ठाकुर नहीं हैं। इसलिये मुझे विनम्र निवेदन करना है कि ठाकुरों की सरकार में मैंने सरकारी आवास आवंटन के लिये जो आवेदन फार्म भरा था, उसे मुझे वापस लौटाया जाये, ताकि मैं उसको ठीक से मढ़वाकर अपने किराये के आवास में टांग सकूं। समय कटता रहा, इसी बीच ठाकुर जी ने बताया कि अब यूपी में ठाकुरों की सरकार है। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब दीक्षित जी ने भी कहा कि ठाकुरों की सरकार है, तब मैंने भरोसा कर लिया। 2018 में मैंने फिर से सरकारी आवास आवंटन के लिये फार्म भर दिया। इस बार भीतर से खुशी थी कि ठाकुरों की सरकार है, इस सरकार में तो आवास आवंटन हो ही जायेगा। पत्नी ने भी सपने देख लिये कि इस बार तो कैसे भी सोफासेट ले ही लिया जायेगा, क्योंकि किराये का पैसा भी बचेगा और जगह भी किराये के घर से ज्यादा होगी। मेहमान आते हैं तो प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाना अच्छा नहीं लगता है। उसने इसी उम्मीद में ब्रह्म बाबा को डेढ़ पाव मिठाई और ग्यारह रुपये भी मान लिया। ब्रह्म बाबा को मनौती माने जाने की खुशी में मैं पनीर ले गया, पत्नी ने कढ़ाई पनीर विथ रायता बनाया। हमलोग खुशी से खाये। अब हमलोगों के बीच लड़ाई कम हो गई थी, क्योंकि ठाकुरों की सरकार थी, और सरकारी आवास भी मिलने ही वाला था। पाठक जी के सपोर्ट से हम फिर से मैदान में डंट गये, लेकिन इसी बीच सरकार ने सरकारी आवास आवंटन के लिये हमलोगों को औचित्यविहीन पाया। औचित्यविहीन टाइप तो हमको भी पाया गया था, लेकिन हम तो ठहरे छोटे पत्रकार, पर हमको खुशी इस बात की थी कि साला आजतक वाला, जागरण वाला, हिंदुस्तान वाला, एबीपी वाला और भी कई बड़का वाला पत्रकार भी औचित्यहीन पाया गया है। हम अब नाउम्मीद हो ही रहे थे कि त्रिपाठीजी ने कहा कि यह ठाकुरों की सरकार है। हमने जोश में आकर फिर से सरकारी आवास आवंटन के लिये फार्म भर दिया। इंतजार करते करते मात्र दो साल बाद ही एक और आवास आवंटन मीटिंग हो गई। त्रिपाठीजी, पांडेयजी, वाजपेयीजी को मकान आवंटित हो गया। हमारे जैसा ठाकुर इस ठाकुर सरकार में भी ताकते रह गया।

पंकज सीबी मिश्रा
जौनपुर, यूपी

घूँघट की बगावत

31 अगस्त 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

आजीवन सच्चे प्यार से वंचित रहीं सिम्मी ग्रेवाल

सिमी ग्रेवाल ना.सिर्फ अभिनेत्री है बल्कि रईसी के मामले में भी उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। फिल्म जगत में एक मात्र वह अभिनेत्री थी जिनकी अमीरी के किस्से सुनाए जाते थे। बहुत कम लोग ही जानते होगे कि सिमी ग्रेवाल आज 16 वर्ष घरे कर चुकी है। फिर भी एक नजर से देखा जाए तो वे आज भी तीस साल की मालुम पड़ती है। उन्हें देखकर आप सदमे में चले जाओगे? मला ऐसी भी कोई महिला हो सकती है, लोग उन्हें अक्सर बुढ़ापे में जबान दिखने का राज पूछते है। इस सवाल का जवाब भी दे दिया था। वे कहती हैं अगर आप डाइट सेहत और शरीर पर ध्यान देते हो तो चेहरे की चमक कभी कम नहीं होगी। ये हुई उनकी खूबसूरती की बात।

एक गौरवशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि :

सिमी ग्रेवाल का पूरा परिवार आग से जुड़ा हुआ है। उनके दादा कलाम केहर सिंह ग्रेवाल क्वीन विक्टोरिया के एडीसी थे। एडीसी को आप पर्सनल सेकेट्री कह सकते है। सिमी ग्रेवाल ने अपने दादा जी को देखा तो नहीं था लेकिन सिमी बनाती है कि वे अपने सारे बच्चों को आर्मी में भेजना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। उनके पास क्वीन विक्टोरिया की दी हुई तलवार भी थी। इसके बाद उनके सगे मामा कर्नल भूपेंद्र सिंह, चचेरे भाई मेजर जनरल गगनजीत सिंह, दूर के रिश्तेदार वाले माया ले. जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत इन लोगों का भी गौरवशाली इतिहास रहा है। ले. ज. प्रेमेन्द्र सिंह भगत पहले भारतीय अफसर आर्मी थे जिन्हें दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान विक्टोरिया क्रॉस मिला था। सिमी का कहना है कि इन तीनों के अलावा भारत, भूमि के लिए सेवा प्रदान करने वाले और भी बहुत सारे रिश्तेदार थे । अब, सिमी की माता जी के बारे में और करते हैं- यहां यह सवाल आया होगा कि- बेटी जब इतनी खूबसूरत है तो मां भी ध खूबसूरत होनी चाहिए। जी हां उनकी मां दर्शी भी बहुत खूबसूरत महिला हुआ करती थीं। उनका अवतार देख कर अंदाजा लग ही गया होगा कि दर्शी एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखने वाली महिला थीं। भारत के दूर दर्शी पंथ प्रधान जवाहर लाल नेहरू के साथ उनकी ये तस्वीर देख देख कर आप अंदाजा लगा सकते है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनके गहरे रिश्ते थे। यहां तक महारानी गायत्री देवी तो उनकी खास सहेली थी 'खुद सिमी ग्रेवाल ने अपनी मां के बोर में कहा था कि मेरी मां दर्शा एक समझदार, बहुत ही सौम्य और पूरी तरह से स्त्रीवाद से भरी हुई महिला थीं। जोगी असे एक बार मिलता उनके गर्म जोशी और शालीनता कभी नहीं भूलता। दिल से कहूं तो मैंने कभी उन्हें ऊंची आवाज में बोलते या किसी से सख्ती से बात करते नहीं सुना सबसे बढ़कर उनका बिना शर्त प्यार और अपनापन ही हमें ताकत देता था। उनमें बहुत आकर्षण था । मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहते हैं - तुम अपनी मां जैसी क्यों नहीं हो। दरअसल में कोशिश करती हूं लेकिन उनका स्तर बहुत ऊंचा है। दुःखद है कि मेरी मां 64वे उम्र में विदा हो गई।

सिमी ग्रेवाल के पिता

सिमी के पिताजी बिग्रेडियर-जलबार सिंह ग्रेवाल आजाद भारत के शुरूआती दौर के बड़े ओहदे वाले सेनानी थे। सिमी के अनुसार उनके पिता जी पोलो खेल के महारथी थे साथ ही वे ढेर सारी भाषा भी बोलाते थे। व्यस्त शेड्यूल में भी वे अपने दो बेटियों को पूरा समय देने की कोशिश करते थे। बतादें कि सिमी ग्रेवाल बड़ी बहन अमृता भी अपनी मां जैसी हैं।

सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को वुधियाना में हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनकी माता ने अमृता से कहा था कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। और तुम्हें आजीवन इसका ख्याल रखना है। सिमी कहती हैं कि उनकी बड़ी बहन आज भी मां को दिया गया वादा निभा रह दा निभा रही है। अमृता एक बड़ी बहन के रूप में उनकी मां भी हैं। घर संभालने से लेकर बिजनेस संभालने तक हर काम में अमृता का बड़ा योगदान रहता है। सिमी ग्रेवाल अभिमान से कहती हैं कि अगर उनका कद ऊंचा हो जाए के समझ लीजिए उन्होंने मुझे अपने कंधों पर लिया है। 2023 मे सिम्मी ग्रेवाल को इंडियन टेलिविजन एकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला था उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी- मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मैंने बॉलीवुड में कदम रखा। मैं ढेर सारे सपनों के साथ । अपनी मुझे आज भी याद है जब में पहली बार अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए फिल्म स्टूडियो में गई थी। तब इस सिनेमा का जादू 'मेरे सामने आया और मैं उसमें खो गई उसके बाद सिनेमा मेरे लिए प्यार बन जैसे-ज्यादातर लव स्टोरी में ख्वाब होते हैं और दिल को तकलीफें होती है-वैसे ही यहां निराशा और शनदार कामयाबी दोनों का सामना हुआ मेरा छोटा-सा सपना अब बड़ा बन गया था लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूं। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी है-'जुनून और समर्थन । जुनून मेरा था लेकिन जो मजबूत समर्थन मिला वह मेरी बहन अमृता का था। फिल्मों में चमकने से पहले सिमी ने सिर्फ एक फिल्म देखी थी आवारा। तब वह पांच साल की थीं। जैसे-जैसे जब वह बड़ी हुईं वैसे वैसे फिल्मों के लिए उनके मन में फिल्मों के लिए संवेदना जागने लगी।इसमें कोई दो राय नहीं था कि- उनके माता पिता ने उन्हें अभिनय करने के लिए रोका होगा। वैसे उनका सारा बचपन लंदन में बीता था। वहां के पीकनम स्टूडियो के वर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए उन्होंने सुपर स्टार एक्ट्रेस बनने का सपना देखा। बाद में उन्होंने सपनों की दुनिया थानी मुंबई आ गई रतन टाटा के अलावा उनका कोई नहीं था। यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने माता पिता के सामने ही घर में ही अनशन भी किया था। आखिरकार उन्हें एक साल की मोहलत मिली। उस वक्त सिमी मात्र 15 साल की थीं। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने अलग-अलग स्टूडियो में ऑडिशन दिए। सिमी ग्रेवाल के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ हिन्दी शब्दों की क्योंकि उनका पूरा बचपन विदेश में बीता, इसलिए हिन्दी की उन्हें कोई समझ नहीं थी इसी परेशानी के कारण उन्हें एक साल तक संघर्ष करना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी फिल्म- तीन देवियां थी। इससे पहले किसी भी फिल्मकार ने उन्हें बड़ा रोल ऑफर नहीं किया।

1965 में रिलीज हुई तीन देवियां फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया। इस फिल्म के बाद उन्हें बड़े बैनर की फिल्में मिलने लगी। जैसे-दो बदन एक रात, आदमी, बंगाली फिल्म अरण्य दिन रात्रि, नाइट इन कलकत्ता इन फिल्मों से पहले तो उन्हें मात्र कुछ सेकेण्ड वाली भूमिकाएं मिलती थी। वो किरदार इंग्लिश वाले थे इसलिए सिम्मी को कास्ट किया जाता था। उनके नाम थे- सन ऑफ इंडिया' टार्जन गोज टु इंडिया, राज की बात. विद्यापति जौहर महमूद गोवा। खैर, हिन्दी सीखने के बाद तो उन्हें लगातार काम मिलता गया। उनकी सबसे बड़ी फिल्म थी मेरा नाम जोकर और अंदाज सिमी ग्रेवाल को फिल्मी जगत ने जितनी कामयाबी दी उतना ही दर्द भी दिया। उन्हें आजीवन सच्चे प्यार से वंचित रहना पड़ा` बजाय इसके कि उनके जीवन में एक से अधिक जीवनसाथी आकर चले गए। उनमें से सबसे बड़ा नाम - मंसूर अली खान का था। रतन टाटा का नाम भी जोड़ा गया। इसके अलावा पाकिस्तान के व्यवसायी सलमान तासिर को लेकर भी खूब चर्चा में रही। अंततः उन्होंने रवि मोहन से शादी कर ली। दुर्भाग्य से ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली- सिमी ग्रेवाल का व्यक्तिगत जीवन उथल-पुथल से भरा था इसका सामना करने की ताकत उन्हें अपनी बहुत अम्रता से मिली।

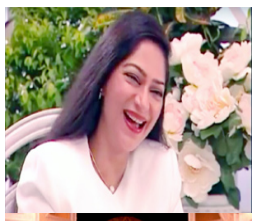

अभिनेता राजेश केशव को दिल का दौरा पड़ा, वेंटिलेटर पर ज़िंदगी की जंग

कोच्चि। मलयालम अभिनेता और टेलीविजन प्रस्तोता राजेश केशव, जिन्हें आरके के नाम से जाना जाता है, बीते रविवार रात कोच्चि के क्राउन प्लाजा होटल में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान मंच पर गिर पड़े। उन्हें लेकशोर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। 47 वर्षीय राजेश केशव अभी वेंटिलेटर पर हैं। फिल्म निर्माता प्रताप जयलक्ष्मी ने उनकी हालत के बारे में फेसबुक पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राजेश की एंजियोप्लास्टी हुई है और तब से वे वेंटिलेटर की मदद से जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। फेसबुक पर उन्होंने लिखा, तब से, उन्हें वेंटिलेटर की मदद से ज़िंदा रखा गया है। उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है—सिर्फ.बीच-बीच में हल्की-फुल्की हरकतें। डॉक्टरों को शक है कि इस स्थिति के कारण उनके मस्तिष्क को हल्का नुकसान पहुँचा है। फिल्म निर्माता के अनुसार, अब हमें एहसास हो गया है कि उन्हें वापस ज़िंदा होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्यार और दुआओं की है। जो कभी अपने अभिनय से मंच पर बिजली सी चमका देता था, अब मशीनों के सहारे बेसुध पड़ा है। यह बेहद दुखद है। लेकिन हम जानते हैं कि वह वापस आएँगे—अगर हम सब मिलकर उन्हें याद करें। उन्हें जरूर लौटना होगा। वह लौटेंगे। प्लीज वापस आ जाओ, मेरे प्यारे दोस्त।

फिल्म निर्माता ने प्रशंसकों और फॉलोअर्स से राजेश के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने नोट के अंत में लिखा, अब उन्हें सिर्फ. दवा की नहीं, बल्कि हमारे प्यार और प्रार्थनाओं की अजेय शक्ति की जरूरत है। अगर हम उन्हें अपने दिल में विश्वास के साथ थामे रहें, तो वे फिर से उठ खड़े होंगे। उन्हें उठना ही होगा। क्योंकि राजेश जैसा कोई व्यक्ति शो के बीच में कभी नहीं जा सकता। राजेश केशव, जिन्हें आरके के नाम से भी जाना जाता है, ने कई भारतीय फीचर फि ल्मों में काम किया है और डिज्नी, स्टार, सन और जी नेटवर्क्स जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए टेलीविजन शो होस्ट किए हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आखिर कब तक.....

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी की भी मजाक उड़ाना या उपहास का पात्र बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले कुछ सालों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आम होता जा रहा है। यहां तक कि स्वतंत्रता के नाम पर समाज में वैमनस्य बढ़ाना, वर्ग विशेष के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करना, धार्मिक भावनाओं को आहत करना इन उपहास कताओं के लिए तो सामान्य होता जा रहा है तो राजनीतिक व सोशल एक्टिविस्ट भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की सरकार को गाइड लाईन जारी कर सीमाओं में बांधने और इस तरह के इन्फ्लूएंसरों के खिलाफ सख्त टिप्पणी व उसी स्तर की सार्वजनिक माफी मांगने के निर्देश आवश्यक हो गए थे। हालांकि यह आदेश स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी एसएमए से पीड़ित व्यक्तियों का समय रैना व अन्य द्वारा उपहास उड़ाने से संबंधित प्रकरण में दिए गए हैं। आदेश में दिव्यांगों का उपहास करने को गंभीरता से लिया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिस स्तर पर उपहास उड़ाया गया ठीक उसी स्तर पर माफी भी मांगी जाए। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि माफी की औपचारिकता से काम नहीं चलने वाला है।

व्यूअरशिप, फोलोवर्स या व्यूज बढ़ाने के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया या यों कहे कि इंटरनेटी संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी को भी उपहास का पात्र बनाना आम होता जा रहा है, उस पर लगाम की आवश्यकता लंबे समय से चली आ रही थी और ऐसे में देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची द्वारा की गई टिप्पणी ऐसे तत्वों और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल फूहड हास्य कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रस्तुत सामग्री में मीडिया इन्फ्लूएंसरों द्वारा लोगों का बैखोफ उपहास उड़ाया जाना आम होता जा रहा है। ऐसे लोग अपने आपको समाज के विशिष्ट व्यक्ति बनने और दिखाने का प्रयास करते हैं। दावा करते

है कि उनके इतने फोलोवर्स है या इतने व्यूअर्स है। पर सवाल यह उठता है कि किसी की मजाक उडाने या उपहास करने का अधिकारी आपको कौन देता है। हेट स्पीच और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के दुष्परिणाम सामने हैं। छोटी सी टिप्पणी कभी कभी तो असामाजिक तत्वों के लिए अच्छा अवसर बन जाती है और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने तक की सीमा तक पहुंच जाती है। मजे की बात यह है कि हेट स्पीच या ऐसी टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई होते ही तथाकथित वुद्धिजीवियों की टीम सक्रिय हो जाती है।

यह तथाकथित कोमेडियन और सोशल इन्फ्लूएंसर अपनी टिप्पणियों की बदौलत व्यूअरशिप बढ़ाते हैं और अनाप शनाप पैसा कमाते हैं, अपनी जेब भरते है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत टिप्पणी नहीं मानते हुए व्यावसायिक गतिविधि करार दिया है। वैसे भी सामान्य नैतिकता का सवाल भी यह उठता है कि आपकों किसी अन्य की विकलांगता या अन्य टिप्पणी को अधिकार कैसे मिल सकता है। कैसे आप किसी को उपहास का पात्र बना सकते हैं तो कैसे आप अनर्गल टिप्पणी कर सकते हैं। हालांकि आजकल हेट स्पीच को लेकर तो न्यायालयों में जाने का चलन बढ़ा है और यह जरुरी भी हो जाता है। सोशल मीडिया के नाम पर आप किसी की निजता पर कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं।

यह निर्णय इस मायने में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि कामेडियन्स या इन्फ्लूएंसर्स द्वारा जिस तरह से इस तरह की गतिविधियां आम होती जा रही है उस पर सख्त लगाम कसना जरुरी हो जाता है। यदि इसी मामलें को देखा जाए तो एक तो ऐसे व्यक्तियों के साथ वैसे ही अन्याय हुआ है और फिर उस शारीरिक विकलांगता का मजाक उड़ाना या निशाना बनाना कहां की नेतिकता हो सकती है। इसके अलावा इंस्ट्राग्राम, वाट्सएप इसी तरह के सोशल मीडिया साइट पर अनर्गल टिप्पणियां या किसी घटना विशेष पर इस तरह की प्रतिक्रिया देकर तनाव के हालात पैदा कर देना या इसी तरह के हालात पैदा करने से आपका शौक तो पूरा हो जाता है पर उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म को सीमाओं में बांधना जरुरी हो जाता है। शहरों में आए दिन दंगे तनाव के हालात बनना आम होता जा रहा है। न्यायालय की टिप्पणी के मध्येनजर सोशल मीडिया प्लेटफार्म संचालकों को भी इस तरह की टिप्पणियों या सामग्री को फिल्टर करने आगे आना चाहिए। अभी तो होता यह है कि चाहे किसी भी तरह की रील हो यदि उसकी व्यूअरशिप ठीक आ जाती है तो कमाई का माध्यम बन जाती है जबकि होना यह चाहिए कि ऐसे इन्फ्लूएंसरों पर सख्ती होने के साथ ही साथ इस तरह की टिप्पणी या रील उसी व्यक्ति द्वारा करने पर ऐसे अकांउट को ब्लेक लिस्ट करते हुए ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कर दिया है। देर सबेर सरकार भी गाइडलाइन जारी कर देगी। हो सकता है सख्त प्रावधान भी कर दे पर समस्या का समाधान आसानी से होता लगता नहीं हैं। ऐसे में आम आदमी को भी आगे आना होगा तो गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनओं और खासतौर से तथाकथित वुद्धिजीवियों को सकारात्मक सोच के साथ आगे आना होगा तभी कामेडियनों और सोशल इन्फ्लूएंसरों पर प्रभावी रोक संभव हो सकेगी।

एक साथ दिखे गोविंदा और सुनीता, तलाक की अफवाहों को किया खारिज

मुंबई। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें कुछ समय से चल रही थीं। लेकिन, गणेश चतुर्थी पर दोनों ने अपने बेटे यशवर्धन के साथ मिलकर इस अफवाह को गलत साबित कर दिया। तलाक की खबरों का खंडन करते हुए सुनीता ने कहा, 'अगर कुछ हुआ होता, तो आज हम इतने करीब नहीं होते। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा गोविंदा सिर्फ.मेरा है। जब तक हम कुछ न कहें, कृपया इस बारे में कुछ न बोलें।' उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा के करियर की शुरूआत से ही उनके घर में गणपति की स्थापना की परंपरा रही है। सुनीता ने बताया कि इस साल उनके बेटे यशवर्धन की फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए उन्होंने यशवर्धन से गणपति की स्थापना करवाई। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनका बेटा भी अपने पिता की तरह नाम, सम्मान और प्यार कमाएगा।

बतादें कि पिछले साल दिसंबर में सुनीता द्वारा बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर करने की अपुष्ट खबरें सामने आई थीं, जिसने इन अफवाहों को और हवा दी। लेकिन, गणेश चतुर्थी के दौरान परिवार की एकजुटता ने इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया। गोविंदा और उनके परिवार ने इस मौके पर बाहर जमा हुए पत्रकारों को मिठाइयां भी बांटी।

एक्टर विशाल की सगाई

साउथ इंडस्ट्री के एक्टर विशाल ने सगाई कर ली है। उनकी मंगेतर एक्ट्रेस साई धनशिका हैं। एक्टर ने ये सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ खुशखबरी शेयर की। इस साल मई में ही दोनों ने अपने रिश्ते का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। जब से इस बात का पता चला था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, तभी से ही उनके फैंस दोनों की शादी का इंतजार कर रहे थे। विशाल ने अपने जन्मदिन पर इसकी खबर फैंस को सुनाई, जो काफी खुश हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें बधाई देते दिख रहे हैं।

जान्हवी कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने मीठी रोमांटिक कॉमेडी के साथ लोगों का किया मनोरंजन

दो विपरीत संस्कृतियों की पृष्ठभूमि पर आधारित, 'परम सुंदरी' सिद्धार्थ मल्होत्रा द्वारा अभिनीत एक उत्साही दिल्ली के लड़के परम और जान्हवी कपूर द्वारा अभिनीत एक आधुनिक मलयाली लड़की सुंदरी की कहानी कहती है। परम सचदेव (सिद्धार्थ) एक निवेशक हैं। वह अपने पिता (संजय कपूर) के साथ दिल्ली में रहते हैं। कई असफल व्यवसायों के बाद, परम को रफाइंड माई सोलमेटस नामक एक डेटिंग ऐप का पता चलता है। परम को इसकी प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल उसे पसंद आता है। वह अपने पिता को इस उद्यम में 5 करोड़ रुपये निवेश करने के लिए मना लेता है। यह साबित करने के लिए कि डेटिंग ऐप सफल हो सकता है, परम केरल में एक लड़की से मिलता है, जो ऐप के अनुसार, उसके लिए एकदम सही मैच है। कम उम्मीदों के साथ, वह अपने दोस्त (मनजोत सिंह) के साथ दक्षिण के एक छोटे से शहर की यात्रा करता है।

ठेक्केपाट्टू सुंदरी दामोदर पिल्लई (जान्हवी कपूर) वह लड़की है जिसकी उसे तलाश है। माता-पिता की मृत्यु के बाद, उसने अपनी हवेली को होमस्टे में बदल दिया है। सुंदरी की एक छोटी बहन, अमु (इनायत वर्मा) है। शुरूआत में, वह परम और उसके दोस्त की केरल और दक्षिण भारत के बारे में रूढ़िवादी समझ से चिढ़ती है। धीरे-धीरे, यह दूरी कम होती जाती है, लेकिन सुंदरी यह जानकर ठगा हुआ महसूस करती है कि परम का उसके होमस्टे पर आना एक मकसद है। क्या अंत में प्यार की जीत होती है? क्या इस नए हीर-

रांझा का सुखद अंत होगा? परम सुंदरी 136 मिनट में इन सवालों के जवाब देती है।

ऐसी है फिल्म

परम सुंदरी एक सरल और प्यारी प्रेम कहानी है। इस क्रॉस-कल्चरल रोमांटिक कॉमेडी के लिए तुषार का विजन स्पष्ट है, और वह इस शैली से जो अपेक्षा की जाती है, उस पर कायम रहते हैं। सीधी-सादी कहानी, साफ-सुथरे मनोरंजन और पूरी तरह से आकर्षक पलों के साथ निखरती है। परम सुंदरी एक फिल्मी फिल्म है। यह बॉलीवुड और उसकी रोमांटिक फिल्मों की विरासत का जश्न मनाती है। यह एक ऐसी फि ल्म है जिसमें दर्शकों को भावनाओं, दृश्यात्मक आकर्षण, सूक्ष्म पूवार्नुमान और प्रेम के बेपरवाह स्वभाव के आगे समर्पण करना पड़ता है।

परम सुंदरी तब सबसे ज्यादा सफल होती है जब यह सिनेमा के गैर-गंभीर स्वरूप को उजागर करती है। जब अविश्वास और हास्य प्रमुखता से सामने आते हैं, तो यह जीत की साझेदारी होती है। कुछ चुटकुले सही बैठते हैं। कलारीपयट्टू और वल्लम काली जैसे कुछ दृश्य इसे मनोरंजक बनाते हैं।

एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी होने के बावजूद, परम सुंदरी में कोई ऐसा रोमांचक संघर्ष नहीं है जो किरदारों के लिए दिल खोलकर समर्थन कर सके। किरदारों, खास-ाकर सुंदरी की पृष्ठभूमि, ने वजन और ऊर्जा बढ़ाई होती। संघर्ष पैदा करने के लिए जोड़े गए उप-कथानक एक रोमांटिक फिल्म के लिए जरूरी चिंगारी पैदा करने और स्क्रीन को आतिशबाजी से जगमगाने में नाकाम रहे।

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का टीजर रिलीज

मुंबई। दर्शकों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। धर्मा प्रोडक्शन की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का मजेदार टीजर रिलीज कर दिया गया है। शशांक खेतान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं। टीजर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया है। बताते चलें कि धर्मा प्रोडक्शन ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर 1 मिनट का टीजर शेयर किया और कैप्शन में लिखा कि चार लोग, दो दिल तोड़ने वाले, एक शादी। टीजर की शुरूआत वरुण धवन के मस्ती भरे अंदाज से होती है, जहां वे बाहुबली जैसे अवतार में दिखाई देते हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com